facebook.com/thebharatshri
twitter.com/thebharatshri
website thebharatshri

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 04 अगस्त 2025 ● वर्ष 7 ● अंक 02 ● मूल्यः 5 रुपए

थायरॉइड समस्या का...

सद्गुरु की कृपा से यदि साधक बीज मंत्र के अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर ले तो मंत्र योग संहिता के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति सहज हो जाती है।

पेज-10-11

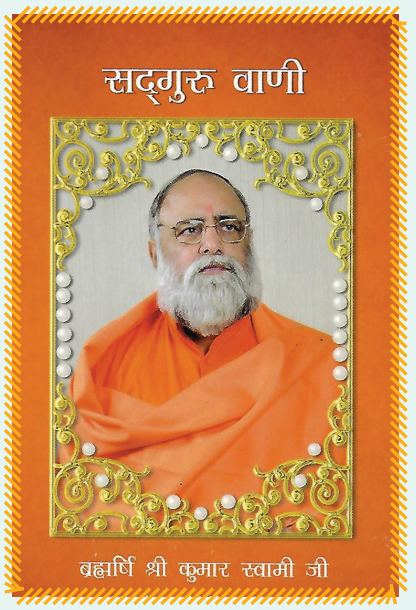

कागज को सीने ला मैने आज समेटा पैमाना। ढूंढ-ढूंढ शब्दों की मदिरा सेवन करता दीवाना। शुद्ध-अशुद्ध कलुषित भाषा ही साकी है मदिरालय की, विश्व समर्पित करता तुमको काव्य रचना।

●

चिरंजीव हो मादक मदिरा जिसमें छलके पैमाना। चिरंजीव हो प्रेरक जिसने मुझे बनाया दिवाना। चिरंजीव हो साकी मेरा मुझ को मय देने वाला, चिरंजीव हो पीने वाला चिरंजीव हो।

महादेव की कृपा से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ

काशी से पीएम मोदी का संदेश

@ भारतश्री ब्यूरो

सावन के पवित्र महीने में बनौली गांव की धरती पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से "नमः पार्वती पतये, हर-हर महादेव" का उद्घोष कर सभा की शुरुआत की। भाषण की शुरुआत भोजपुरी में कर उन्होंने काशी के लोगों को अपने 'परिवारजन' बताते हुए कहा "सावन के पावन महीने में आज हमके काशी के हमरे परिवार के लोगन से मिले के अवसर मिलल हौ। हम काशी के हर परिवारजन के प्रणाम करत हई।" इस अवसर पर पीएम मोदी ने कुल 52 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें बुनियादी ढाँचे से लेकर पेयजल, किसानों और उद्योग से जुड़े काम शामिल हैं। 54 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने 10 बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी।

ऑपरेशन सिंदूर वादे से अंजाम तक

पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि "ऑपरेशन सिंदूर महादेव और मां गंगा के आशीर्वाद से ही सफल हो पाया। मैंने अपनी बहनों के सिंदूर का बदला ले लिया, जो कहा था वह किया।" उन्होंने इस सफल अभियान को देश की बेटियों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

यादव बंधुओं के जलाभिषेक की अनोखी परंपरा

सावन के माहौल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा विश्वनाथ का यादव बंधुओं द्वारा किया गया जलाभिषेक एक अद्भुत और विहंगम दृश्य था। यह परंपरा, जो वर्षों से चली आ रही है, केवल काशी में ही देखने को मिलती है। उन्होंने मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की सराहना की, जिन्होंने लाखों भक्तों के आगमन के बीच सुचारु व्यवस्था बनाए रखी।

9.70 करोड़ किसानों को मिला लाभ

किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। इस बार 20,500 करोड़ रुपये की राशि देशभर के किसानों के खातों में सीधे भेजी गई। इसमें 2.21 लाख किसान काशी के भी शामिल हैं।

उन्होंने याद दिलाया कि 18 जून 2024 को भी 9.26 करोड़ किसानों के खाते में धनराशि भेजी गई थी। "हमारा प्रयास है कि किसानों की मेहनत का सम्मान हो और उन्हें समय पर आर्थिक सहयोग मिले।"

जल जीवन मिशन और सड़क परियोजनाएं

प्रधानमंत्री ने 269.10 करोड़ की लागत से तैयार वाराणसी-भदोही फोरलेन मार्ग का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रयागराज समेत पूर्वांचल के कई जिलों – जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया में यात्रा सुगम होगी।इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिन पर 129.97 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा "हमारे गांवों की माताओं-बहनों को अब पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।"

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर

देश की आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा "भारतवासी अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को अपनाने की आदत डालें। हम तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं।"उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत अपनी नीतियों और आत्मनिर्भरता के दम पर दुनिया में अलग पहचान बना रहा है।

गंगईकोंडा चोलपुरम की शिवभक्ति की कथा

तमिलनाडु के ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह चोल काल की भव्य कला और शिवभक्ति का अद्भुत उदाहरण है।उन्होंने बताया कि एक हजार साल पहले महान राजा राजेंद्र चोल ने गंगा जल मंगवाकर उत्तर और दक्षिण को जोड़ा था। "काशी तमिल संगमम के जरिए हम उसी भावना को आज भी जीवित रख रहे हैं।"

युवाओं के लिए प्रतियोगिताओं की अपील

युवा पीढ़ी को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री ने सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और सांसद रोजगार मेला जैसे कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे आयोजनों में जनभागीदारी बढ़ाई जाए और युवाओं को जोड़कर इन्हें सफल बनाया जाए।

MN DIVINE

ORDER ALL TYPES OF :

- POOJA SAMAGRI,
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND PRATIMA.

NOW GET AT YOUR HOME ON

MNDIVINE.COM

ORDER NOW

https://mndivine.com/

HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

प्रेमानंद महाराज को फेसबुक पर मिली जान से मारने की धमकी

साधु-संतों में रोष

महिलाओं पर बयान के बाद मचा विवाद, आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर दी गला काटने की धमकी; हिंदू संगठनों ने कठोर कार्रवाई की मांग की

@ शोभित यादव

वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज को फेसबुक के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पोस्ट में न केवल आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि यहां तक कह डाला कि "अगर वो मेरे घर की बात करता तो मैं उसका गला काट देता।" यह धमकी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और पूरे साधु-संत समाज में आक्रोश का माहौल है।

विवाद की पृष्ठभूमि

हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज ने एक धार्मिक प्रवचन के दौरान युवाओं को मर्यादित आचरण और नैतिक जीवन अपनाने की सलाह दी थी। उन्होंने समाज में बढ़ते गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड संस्कृति पर चिंता जताते हुए इसे सामाजिक संरचना के लिए हानिकारक बताया।

उन्होंने कहा कि "युवाओं को अपने जीवन में संस्कार और संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज के लिए आवश्यक है।"

महाराज के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आने लगीं। जहां एक वर्ग ने उनके विचारों का समर्थन किया, वहीं कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर टिप्पणी बताते हुए विरोध किया। इसी क्रम में एक युवक ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ जान से मारने की धमकी दे दी।

फेसबुक पर धमकी, वीडियो भी वायरल

बताया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज का यह प्रवचन वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है। इसी वीडियो को आधार बनाकर आरोपी युवक ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, "प्रेमानंद महाराज ने जो बात कही है, वह पूरे समाज की बात है, लेकिन अगर वो मेरे घर की बात करता तो मैं उसका गला काट देता।"

यह टिप्पणी तेजी से वायरल हुई और कई धार्मिक संगठनों तथा भक्तों तक पहुंच गई। देखते ही देखते यह मामला साधु-संतों और हिंदूवादी संगठनों के बीच चर्चा का विषय बन गया।

साधु-संत समाज का आक्रोश

धमकी की जानकारी मिलते ही वृंदावन और आसपास के धार्मिक समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलारी बाबा ने कहा, "अगर कोई व्यक्ति प्रेमानंद बाबा की तरफ आंख उठाकर देखेगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगाकर संत समाज की रक्षा करेंगे। किसी भी अपराधी की गोली को अपनी छाती पर खाने के लिए हम तैयार हैं।"

फलारी बाबा ने सरकार और प्रशासन से कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ उदाहरणात्मक दंड दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी संतों के सम्मान पर आंच न डाल सके।

वहीं महंत रामदास जी ने इस घटना को संत समाज और धार्मिक मर्यादा पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा, "गाय, कन्या और साधु तीनों की रक्षा समाज की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। जो भी व्यक्ति प्रेमानंद बाबा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करेगा, उसे साधु समाज कभी नहीं छोड़ेगा।"

प्रसिद्ध संत हैं प्रेमानंद महाराज

प्रेमानंद महाराज वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत हैं, जो अपने प्रवचनों में भक्ति, संस्कार और संयमित जीवन पर जोर देते हैं। देशभर में उनके अनुयायियों की बड़ी संख्या है।उनके प्रवचन अक्सर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर प्रसारित होते हैं और वे विशेष रूप से युवाओं को नैतिक जीवन और धर्म के प्रति प्रेरित करने के लिए जाने जाते हैं।

कानूनी कार्रवाई की मांग

इस घटना ने न केवल धार्मिक समुदाय को झकझोर दिया है बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई यूजर्स ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कार्रवाई की मांग की है।

कानूनी जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी को जान से मारने की धमकी देना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए आरोपी को सात साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

सोशल मीडिया पर बढ़ते अपराध

यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस हद तक जिम्मेदारी के साथ हो रहा है। हाल के वर्षों में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भड़काऊ पोस्ट, आपत्तिजनक टिप्पणियां और धमकियां तेजी से बढ़ी हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे मामलों में त्वरित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को मजबूत करना चाहिए, ताकि विवाद बढ़ने से पहले ही उचित कदम उठाए जा सकें।

भक्तों में है भारी नाराजगी

प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों ने धमकी की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। भक्तों का कहना है कि महाराज के विचार समाज सुधार की दिशा में हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के लिए।

एक भक्त ने कहा, "महाराज हमारे गुरु हैं। उनके खिलाफ इस तरह की भाषा असहनीय है। हम चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे।"

प्रशासन की भूमिका पर है नजर

स्थानीय पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की पहचान के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को मिली धमकी केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक मर्यादाओं पर भी चुनौती है। यह घटना बताती है कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना आज के समय में कितना जरूरी है।जहां एक ओर समाज को अपने संतों और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर किसी भी तरह की असहमति को हिंसा या धमकी की भाषा में व्यक्त करना कानूनन और नैतिक रूप से गलत है।अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है।

तेजस्वी के दो वोटर कार्ड का मामला

चुनाव आयोग की सख्ती, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

RJD नेता ने लगाया नाम कटने का आरोप, आयोग ने कहा– लिस्ट में दर्ज है नाम, दूसरा EPIC नंबर आधिकारिक नहीं

@ आनंद मीणा

राजनीतिक गलियारों में रविवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब चुनाव आयोग ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया। मामला सीधा-सीधा मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी से जुड़ा है। आयोग के मुताबिक, तेजस्वी यादव के पास दो अलग-अलग EPIC (Electors Photo Identity Card) नंबर पाए गए हैं। इनमें से एक नंबर आधिकारिक रिकॉर्ड में है, जबकि दूसरा नंबर जारी ही नहीं किया गया।चुनाव आयोग ने नोटिस में साफ लिखा है कि उनके पास मौजूद जांच रिपोर्ट के अनुसार तेजस्वी यादव का नाम अब भी वोटर लिस्ट में दर्ज है और उनका आधिकारिक EPIC नंबर RAB0456228 है। वहीं, जिस दूसरे EPIC नंबर RAB2916120 का ज़िक्र तेजस्वी ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, वह कभी भी आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ। आयोग ने इस कार्ड को तुरंत जमा करने के लिए कहा है ताकि उसकी जांच की जा सके।

कैसे सामने आया मामला?

यह मामला तब चर्चा में आया जब तेजस्वी यादव ने प्रेस से बात करते हुए दावा किया कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है और उनका EPIC नंबर बदल दिया गया है। तेजस्वी का आरोप था कि यह कार्रवाई चुनावी साजिश के तहत की गई है। उन्होंने मीडिया के सामने एक अलग EPIC नंबर का हवाला भी दिया।इसके बाद चुनाव आयोग ने जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में ही स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी का नाम पटना की वोटर लिस्ट में अब भी मौजूद है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि उनका नाम बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन में स्थित मतदान केंद्र संख्या 124 में दर्ज है, जहां वे क्रम संख्या 416 पर सूचीबद्ध हैं। इस रिकॉर्ड में उनका EPIC नंबर RAB0456228 है, जिसे उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय भी इस्तेमाल किया था।

आयोग की सख्त टिप्पणी

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों को न केवल गलत बताया, बल्कि इसे भ्रामक भी करार दिया। आयोग के मुताबिक, EPIC नंबर RAB2916120 के जारी होने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके बावजूद, चूंकि इस नंबर का जिक्र तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, आयोग ने उससे संबंधित कार्ड को सौंपने का निर्देश दिया है, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि यह कार्ड कैसे बना और किसने जारी किया।आयोग ने नोटिस में यह भी साफ कर दिया कि यदि इस मामले में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो यह गंभीर चुनावी अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए तय सजा और कानूनी कार्रवाई होगी।

राजनीतिक रंग भी चढ़ा

तेजस्वी यादव के इस आरोप और आयोग की प्रतिक्रिया ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। RJD समर्थकों का कहना है कि यह मामला विपक्षी नेताओं को चुनावी दौड़ से बाहर करने की साजिश है, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि तेजस्वी के आरोप पूरी तरह झूठे हैं और यह महज़ एक राजनीतिक नाटक है।RJD के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "तेजस्वी यादव को परेशान करने के लिए प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले उनका नाम मतदाता सूची से गायब करने की कोशिश की गई और अब उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है।"वहीं, बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा, "सच्चाई यह है कि तेजस्वी यादव के पास दो EPIC नंबर हैं। उन्हें बताना चाहिए कि यह दूसरा कार्ड कैसे बना। जनता को गुमराह करने की बजाय उन्हें पारदर्शी तरीके से जवाब देना चाहिए।"

कानूनी नजरिए से मामला

चुनाव कानून के तहत एक व्यक्ति के पास केवल एक ही मान्य वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। यदि किसी के पास एक से अधिक कार्ड पाए जाते हैं, तो यह Representation of the People Act, 1950 और 1951 के प्रावधानों के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मताधिकार रद्द करने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है।कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि EPIC नंबर RAB2916120 वाकई आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ, तो यह पता लगाना ज़रूरी है कि इसका निर्माण कहां और कैसे हुआ। अगर इसमें कोई फर्जीवाड़ा या डेटा में छेड़छाड़ पाई जाती है, तो मामला न केवल चुनाव आयोग बल्कि पुलिस और साइबर सेल तक जाएगा।

आयोग का पत्र और तेजस्वी की चुप्पी

आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस में तेजस्वी यादव से निर्धारित समय के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर वे निर्धारित अवधि में जवाब नहीं देते, तो आयोग उपलब्ध तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर अगला कदम उठाएगा।अब तक तेजस्वी यादव ने इस नोटिस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि वे मामले की कानूनी तैयारी कर रहे हैं और समय आने पर अपनी सफाई पेश करेंगे।

चुनावी मौसम में बढ़ी सरगर्मी

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची को लेकर बेहद सतर्क हैं। ऐसे में RJD के प्रमुख चेहरे पर वोटर कार्ड से जुड़ा आरोप विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों के लिए बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है।विशेषज्ञ मानते हैं कि इस घटना के दो बड़े असर होंगे। मतदाता सूची और वोटर आईडी से जुड़ी पारदर्शिता पर जनता का ध्यान जाएगा।विपक्ष इसे सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताएगा, जबकि सत्ता पक्ष इसे फर्जीवाड़े के सबूत के तौर पर पेश करेगा। अब गेंद तेजस्वी यादव के पाले में है। उन्हें चुनाव आयोग के सवालों का जवाब देना होगा और यह साबित करना होगा कि उनका दूसरा EPIC नंबर कैसे और किस परिस्थिति में सामने आया। अगर वे यह साबित नहीं कर पाते कि यह उनकी जानकारी के बिना हुआ, तो उन्हें कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।दूसरी ओर, यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि EPIC नंबर RAB2916120 किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्रशासनिक गलती के कारण दर्ज हुआ, तो मामला यहीं खत्म हो सकता है। लेकिन यदि इसमें कोई फर्जीवाड़ा या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो यह बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है।तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी कार्ड वाले मामले ने बिहार की सियासत को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

पहलगाम हमला

शहीद मानने की लड़ाई

26 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 26 आम नागरिकों की जान गई, जिनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। यह 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था। इस घटना ने न केवल देश में गुस्सा और दुख पैदा किया, बल्कि एक नई बहस को भी जन्म दिया—क्या इन मासूम लोगों को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? इस सवाल ने लोकसभा से लेकर आम जनता तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस लेख में हम इस बहस को, विशेष रूप से शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी की भावनात्मक अपील के संदर्भ में, विभिन्न पहलुओं से देखेंगे।

पहलगाम हमला: एक त्रासदी जो भुलाई नहीं जा सकती

पहलगाम, जिसे 'मिनी स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है, अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को बैसारन वैली में पांच आतंकियों ने इस शांति को भंग कर दिया। उन्होंने M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियारों से 26 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे, हालांकि एक ईसाई और एक स्थानीय मुस्लिम भी इस हमले का शिकार हुए। आतंकियों ने धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया। उदाहरण के लिए, शुभम द्विवेदी को आतंकियों ने इस्लामिक कलमा पढ़ने के लिए कहा, और जब वे ऐसा नहीं कर पाए, तो उन्हें गोली मार दी गई।

इस हमले की जिम्मेदारी 'द रेसिस्टेंस फ्रंट' (TRF) ने ली, जो पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक हिस्सा माना जाता है। TRF ने दावा किया कि यह हमला कश्मीर में गैर-स्थानीय लोगों के बसने के खिलाफ था। हालांकि, बाद में उन्होंने इस दावे से इनकार किया, लेकिन भारत सरकार ने इसे उनकी साजिश का हिस्सा बताया। इस हमले ने न केवल पर्यटन को प्रभावित किया, बल्कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को भी बढ़ा दिया।

ऐशान्या की पुकार: 'मेरे पति को शहीद कहो'

29 जुलाई 2025 को लोकसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा के दौरान ऐशान्या द्विवेदी ने एक ऐसी आवाज उठाई, जो हर भारतीय के दिल को छू गई। अपने पति शुभम द्विवेदी, जो इस हमले में मारे गए थे, और अन्य 25 पीड़ितों के लिए उन्होंने 'राष्ट्रीय शहीद' का दर्जा मांगा। ऐशान्या ने कहा, "शुभम ने अपनी जान देश के लिए दी। शहीद कहलाने के लिए और क्या चाहिए?" उनकी यह बात न केवल उनकी निजी पीड़ा को दर्शाती है, बल्कि उन सभी परिवारों की भावनाओं को सामने लाती है, जिन्होंने इस हमले में अपने प्रियजनों को खोया।

ऐशान्या ने नेताओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ नेता इस हमले की गंभीरता को कम कर रहे हैं और इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। उनकी अपील थी, "आतंकियों ने किसी का जाति या पार्टी नहीं पूछी, उन्होंने भारतीयों पर हमला किया।" यह बयान देश में एकता की जरूरत को दर्शाता है। ऐशान्या ने यह भी कहा कि सरकार ने अभी तक पीड़ितों के परिवारों को कोई ठोस मदद या मान्यता नहीं दी। उनकी यह मांग अब एक सामाजिक आंदोलन बन चुकी है।

ऑपरेशन सिंदूर और महादेव: इंसाफ की पहल

पहलगाम हमले के जवाब में भारत सरकार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने "मजबूत, सफल और निर्णायक" बताया। यह ऑपरेशन 22 मिनट में पूरा हुआ और इसका मकसद आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई गलती की, तो यह ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा।

इसके बाद 'ऑपरेशन महादेव' में तीन आतंकियों—सुलेमान, हामजा अफघानी और जिब्रान—को मार गिराया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जुलाई 2025 को लोकसभा में बताया कि ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। उनके पास से मिले हथियारों और गोलियों की फॉरेंसिक जांच से यह पक्का हो गया कि इन्हीं हथियारों से पहलगाम में हमला हुआ था। अमित शाह ने यह भी बताया कि इन आतंकियों के पास पाकिस्तानी वोटर आईडी और पाकिस्तान में बने चॉकलेट्स मिले, जिससे यह साफ हो गया कि वे पाकिस्तानी थे।

ऐशान्या ने ऑपरेशन महादेव की सफलता पर राहत जताई, लेकिन कहा, "दर्द तो नहीं जाएगा, पर थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा।" यह ऑपरेशन पीड़ितों के लिए इंसाफ की दिशा में एक कदम था, लेकिन शहीद का दर्जा अभी भी एक अनसुलझा मुद्दा है।

शहीद का दर्जा: क्यों जरूरी है यह बहस?

भारत में 'शहीद' का दर्जा आमतौर पर उन सैनिकों को दिया जाता है, जो देश के लिए अपनी जान देते हैं। लेकिन पहलगाम हमले ने यह सवाल उठाया कि क्या आम नागरिक, जो आतंकी हमले में मारे जाते हैं, उन्हें भी यह सम्मान मिलना चाहिए? ऐशान्या की मांग ने इस बहस को नया आयाम दिया है। उनके मुताबिक, ये लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वे भारतीय थे। यह एक ऐसा हमला था, जो देश की एकता और शांति पर प्रहार था।

कई लोगों का मानना है कि शहीद का दर्जा देना न केवल पीड़ितों के परिवारों को सम्मान देगा, बल्कि यह देश को एकजुट करने का संदेश भी देगा। दूसरी ओर, कुछ लोग कहते हैं कि शहीद का दर्जा सिर्फ सैन्य बलों के लिए होना चाहिए, ताकि उसका महत्व कम न हो। लेकिन ऐशान्या का तर्क है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर भारतीय एक सैनिक है, चाहे वह सैन्य वर्दी में हो या न हो।

इस बहस ने समाज में एक नई जागरूकता पैदा की है। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग ऐशान्या के समर्थन में हैं, तो कुछ इस दर्जे की परिभाषा पर सवाल उठा रहे हैं। यह बहस अब केवल पहलगाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता का प्रतीक बन चुकी है।

एकता और इंसाफ की राह

पहलगाम हमले ने न केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकता कितनी जरूरी है। ऐशान्या ने अपनी अपील में बार-बार कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि एक साथ खड़े होने का है। उन्होंने कहा, "सेना पर सवाल उठाना या विभाजनकारी बातें करना हमें कमजोर करता है।"

इस हमले के बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दीं, इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित किया और अटारी-वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। इन कदमों ने भारत के सख्त रुख को दिखाया। साथ ही, जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इस हमले की निंदा की और पीड़ितों के लिए एकजुटता दिखाई।

लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम पीड़ितों के परिवारों को सुकून दे पाएंगे? ऐशान्या ने कहा, "मैं 27-28 साल की हूं। लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं कैसे भूलूं कि मैंने अपने पति को खो दिया?" उनकी यह बात उन 26 परिवारों की पीड़ा को दर्शाती है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। सरकार से उनकी मांग है कि पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक और भावनात्मक सहायता दी जाए।

एक नई शुरुआत की जरूरत

पहलगाम हमला और ऐशान्या द्विवेदी की अपील ने भारत में एक नई बहस को जन्म दिया है। यह बहस सिर्फ शहीद के दर्जे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की एकता, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पीड़ितों के प्रति संवेदना की बात करती है। ऐशान्या की आवाज ने न केवल पीड़ितों के परिवारों को बल दिया, बल्कि पूरे देश को एकजुट होने का संदेश दिया।

यह समय है कि सरकार और समाज मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाए। शहीद का दर्जा देना एक प्रतीकात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसके साथ-साथ पीड़ितों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद, पुनर्वास और भावनात्मक सहायता भी जरूरी है। पहलगाम हमला हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर भारतीय की हिस्सेदारी है। इस लड़ाई में हमें न केवल आतंकियों को जवाब देना है, बल्कि अपने लोगों को यह भरोसा भी देना है कि देश उनके साथ है।

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

भारत श्री

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

सोमवार, 04 अगस्त 2025, विक्रम संवत 2080

हम भारत से डरने वाले नहीं

पाकिस्तान के सर्वोच्च सेनाअध्यक्ष ने अमेरिका में जाकर अमेरिका के प्रमुख लोगों के बीच यह बात कही है कि हम भारत से डरने वाले नहीं है । यदि भारत कभी भी पाकिस्तान को कमजोर करेगा या खतरा पैदा करेगा तो हम भारत पर एटम बम का तत्काल प्रयोग करेंगे और उस आइटम बम से सबसे अधिक नुकसान अंबानी परिवार के व्यापार को होगा वहां से हम शुरुआत करेंगे। विचारणीय प्रश्न यह है कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने यह बात अमेरिका में क्यों कहीं क्योंकि इतनी गंभीर बात तो उसे पाकिस्तान में कहानी चाहिए थी अपने शासको के बीच में कहानी चाहिए थी लेकिन उसने अमेरिका को चुना। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है की वर्तमान समय में भारत और ट्रंप के बीच में जो मतभेद चल रहे हैं इस मतभेद में ट्रंप की चापलूसी करने के लिए पाकिस्तान के सेनाअध्यक्ष ने यह बात कही जबकि पाकिस्तान यह अच्छी तरह जानता है कि ट्रंप किस मामले में कितने गंभीर हैं कब किसको धमकी दे देंगे और कब किसके पक्ष में बोल देंगे यह कुछ पता नहीं है। ट्रंप को कोई चापलूसी करके प्रसन्न नहीं कर पाएगा लेकिन फिर भी पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने अपनी तरफ से यह कहने का प्रयास किया । मैं समझता हूं कि भारत में कोई भी इससे डरने वाला नहीं है क्योंकि भारत का बच्चा-बच्चा जानता है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी तो पाकिस्तान के आइटम बम और परमाणु बम भारत के कब्जे में होंगे पाकिस्तान के पास उनका अधिकार रहेगा ही नहीं और वह अगर काम आएंगे तो भारत के काम आएंगे लेकिन फिर भी अभी जब तक पाकिस्तानियों के पास इतनी स्वायत्त है तब तक बोलने में क्या जाता है। मूर्खता की भी कोई हद होती है पाकिस्तान ऐसी मूर्खता करने वाला अ केला नहीं है इस तरह की एटम बम की धमकी तो रुस भी रोज देता है ईरान भी रोज देता है और पता नहीं दुनिया में कौन-कौन एटम बम की धमकी देते हैं जबकि सब लोग जानते हैं कि जो शक्तिशाली होते हैं वह इस तरह धमकी नहीं देते।

बजरंग मुनि

पाकिस्तान को मिला कड़ा संदेश, दुनिया ने देखी भारत की नई रणनीति

@ अनुराग पाठक

लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "ऑपरेशन सिंदूर" सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि भारत की नई सुरक्षा नीति का ऐलान है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को यह ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा,इसके उलट, लगभग सभी बड़े वैश्विक मंचों और शक्तियों ने भारत का समर्थन किया। यूएन के 193 देशों में से केवल तीन देशों ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, जबकि अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ब्रिक्स और क्वॉड जैसे समूहों ने भारत के रुख की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने खुलासा किया कि 9 मई की रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बार-बार उनसे बात करने की कोशिश की और चेताया कि पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी में है। जवाब में मोदी ने साफ कहा"अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम गोली का जवाब गोले से देंगे"। अगले ही दिन, 10 मई की सुबह तक पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को तहस-नहस करने का दावा किया गया।

यह अभियान पाकिस्तान के लिए एक सख्त चेतावनी साबित हुआ।जब तक आतंकवाद का रास्ता बंद नहीं होगा, भारत की कार्रवाई जारी रहेगी। मोदी ने गर्व से कहा कि इस बार भारत वहां पहुंचा जहां पहले कभी नहीं गया था।पाकिस्तान के कोने-कोने में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। बहावलपुर और मुरीदके जैसे ठिकाने, जो दशकों से पाकिस्तान की सरपरस्ती में फल-फूल रहे थे, जमींदोज कर दिए गए। यह भारत का वह जवाब था जिसने पाकिस्तान की तथाकथित न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की हवा निकाल दी।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखे वार किए, 1947 से लेकर 1971 तक के कई अवसर गिनाए जब पीओके, अक्साई चिन, रण ऑफ कच्छ और करतारपुर जैसे इलाकों को वापस लेने का मौका गंवाया गया। हाजीपीर की वापसी, सिंधु जल समझौते और सियाचिन पर कांग्रेस के रुख को भी उन्होंने देशहित के खिलाफ बताया।

इस बार की खासियत यह रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न केवल सामरिक चातुर्य दिखाया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की तकनीकी क्षमता भी पूरी दुनिया के सामने रखी। मेड इन इंडिया ड्रोन और मिसाइलों ने पाकिस्तान के हथियारों की पोल खोल दी।

मोदी के शब्दों में, "सिंधु से सिंदूर तक की कार्रवाई" ने यह सिद्ध कर दिया है कि नया भारत न तो डरता है, न झुकता है, और न ही किसी भी खतरे को अनदेखा करता है। दुनिया ने देख लिया है कि अब आतंक के अड्डों को सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि ठोस जवाब मिलेगा।

जुबानी तीर

"भारत रूसी तेल खरीदकर रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए हम भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा रहे हैं। अमेरिका अपने हितों की रक्षा करेगा — 'अमेरिका फ़र्स्ट' हमारी प्राथमिकता है।

डोनाल्ड ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति)

"हम अपने किसानों, मछुआरों और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। भारत किसी भी अन्यायपूर्ण और एकतरफा निर्णय के आगे नहीं झुकेगा।

नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)

"ट्रंप का यह 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है—भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए डराने-धमकाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमज़ोरी के चलते भारतीय जनता के हितों से समझौता नहीं करना चाहिए।

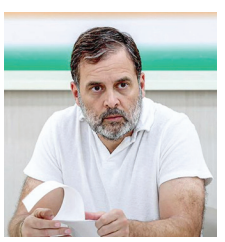

राहुल गांधी(विपक्ष के नेता)

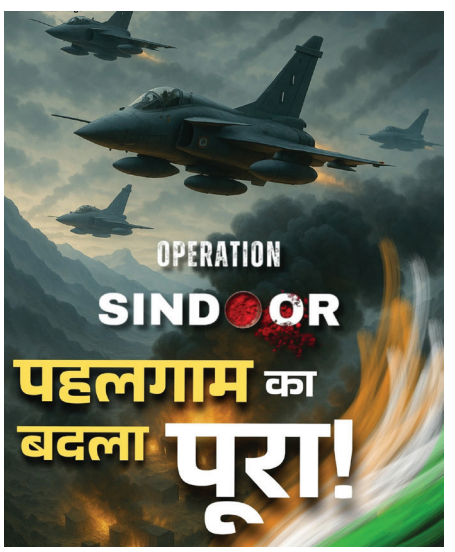

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक डॉ. महिमा मक्कर द्वारा एच0टी0 मीडिया, प्लॉट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा-9 उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं जी. एफ. 5/115, गली नं. 5 संत निरंकारी कालोनी, दिल्ली-110009 से प्रकाशित । संपादकः महिमा मक्कर, RNI No. DELHI/2019/77252, संपर्क 011-43563154

विज्ञापन एवं वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिस के पते पर सम्पर्क करें या फिर इन नम्बरों - 9667793987 या 9667793985 पर बात करें या इस पर media@bharatshri.com ईमेल करें।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

थायरॉइड समस्या का आयुर्वेदिक समाधान

जड़ से इलाज की राह

@ डॉ महिमा मक्कर

आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थायरॉइड एक बेहद आम लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। खासतौर पर महिलाओं में यह विकार तेजी से फैल रहा है। कई बार लोग इसके शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और जब तक समस्या गंभीर रूप लेती है, तब तक उन्हें लंबे समय तक दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में थायरॉइड के लिए मुख्यतः हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या एलोपैथिक दवाएं दी जाती हैं, लेकिन इनका सेवन जीवनभर करना पड़ सकता है और दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ऐसे में आयुर्वेद एक प्राचीन और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के रूप में थायरॉइड विकार के मूल कारण पर काम करता है और शरीर में संतुलन बहाल करने में मदद करता है।

थायरॉइड क्या है और इसका कार्य

गले के सामने, स्वरयंत्र के ठीक नीचे एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जिसे थायरॉइड कहते हैं। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन (T4) और ट्रायआयोडोथायरोनिन (T3) नामक हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा स्तर, हृदय गति, पाचन, मानसिक स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता तक को प्रभावित करते हैं।

थायरॉइड विकार के दो मुख्य प्रकार हैं:

हाइपोथायरॉइडिज्म – जब थायरॉइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बनाती।

लक्षण: थकान, वजन बढ़ना, ठंड असहनीय लगना, सूजन, बाल झड़ना, कब्ज, त्वचा का रूखापन।

हाइपरथायरॉइडिज्म – जब थायरॉइड ग्रंथि अत्यधिक हार्मोन का उत्पादन करती है।

लक्षण: वजन घटना, घबराहट, हृदय की धड़कन तेज होना, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, हाथ कांपना।

आयुर्वेद में थायरॉइड विकार की समझ

आयुर्वेद में शरीर को तीन मुख्य दोषों – वात, पित्त और कफ – के संतुलन पर आधारित माना गया है। थायरॉइड विकार को खासतौर पर वात और कफ दोष के असंतुलन का परिणाम माना जाता है।हाइपोथायरॉइडिज्म में आमतौर पर कफ दोष की वृद्धि और अग्नि (पाचन शक्ति) की मंदता होती है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है।हाइपरथायरॉइडिज्म में पित्त और वात दोष का बढ़ना देखा जाता है, जिससे शरीर की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है।

आयुर्वेदिक उपचार में इन दोषों को संतुलित करने के साथ-साथ अग्नि को मजबूत करना, विषैले तत्वों (आम) को बाहर निकालना और ग्रंथि की कार्यक्षमता सुधारना शामिल है।

थायरॉइड के लिए प्रमुख आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां

अश्वगंधा (Withania somnifera)

यह थायरॉइड हार्मोन के उत्पादन को संतुलित करने में मदद करती है।

तनाव और थकान को कम कर ऊर्जा बढ़ाती है।

हाइपोथायरॉइडिज्म में विशेष रूप से लाभकारी।

गुग्गुल (Commiphora mukul)

मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वजन घटाने में मदद करता है।

हार्मोन संतुलन में सहायक।

कंचनार गूग्गुल

आयुर्वेद में थायरॉइड विकारों का पारंपरिक उपचार।

ग्रंथियों की सूजन को कम करता है और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है।

ब्राह्मी (Bacopa monnieri)

मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्या में राहत देती है।

थायरॉइड विकार से जुड़े मानसिक लक्षणों को कम करती है।

शंखपुष्पी (Convolvulus pluricaulis)

तंत्रिका तंत्र को शांत करती है।

मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाती है।

आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियां

1. पंचकर्म थेरेपी

थायरॉइड के लिए पंचकर्म शरीर से विषैले तत्व निकालकर दोषों का संतुलन करता है।

वमन – अतिरिक्त कफ को निकालना।

विरेचन – पित्त को नियंत्रित करना।

नस्य – नाक के माध्यम से औषधि देना, जिससे मस्तिष्क और गले की ग्रंथियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

2. योग और प्राणायाम

सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन – थायरॉइड ग्रंथि पर दबाव डालकर उसके कार्य में सुधार करते हैं।

भ्रामरी, उज्जायी और अनुलोम-विलोम प्राणायाम – मानसिक तनाव कम करते हैं और हार्मोन संतुलित करते हैं।

3. ध्यान और जीवनशैली में बदलाव

तनाव थायरॉइड विकार का बड़ा कारण है। नियमित ध्यान, पर्याप्त नींद और दिनचर्या में संतुलन जरूरी है।

थायरॉइड रोगियों के लिए आहार संबंधी सुझाव

हाइपोथायरॉइडिज्म में लाभकारी

साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, ताजे फल।

अखरोट, बादाम, अलसी के बीज – इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है।

दूध, दही, घी – सीमित मात्रा में।

हाइपरथायरॉइडिज्म में लाभकारी

ठंडे स्वभाव के खाद्य – खीरा, करेला, लौकी, तरबूज।

प्रोटीन युक्त आहार – मूंग दाल, पनीर, छाछ।

बचने योग्य चीजें

प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, चीनी, अधिक नमक।

हाइपोथायरॉइड में सोया उत्पाद कम लें, क्योंकि यह हार्मोन के अवशोषण में बाधा डाल सकता है।

हाइपरथायरॉइड में कैफीन और मसालेदार चीजों से परहेज।

आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे

अश्वगंधा पाउडर – रोज सुबह-शाम गुनगुने दूध के साथ 1-2 ग्राम लें।

कंचनार गूग्गुल – आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से लें।

गर्म पानी में नींबू और शहद – शरीर की सफाई और मेटाबॉलिज्म सुधारने में मददगार।

तिल का तेल और नारियल पानी – थायरॉइड ग्रंथि को पोषण देता है।

थायरॉइड और मानसिक स्वास्थ्य

थायरॉइड विकार केवल शरीर को ही नहीं, मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। हाइपोथायरॉइड में सुस्ती, अवसाद और भूलने की समस्या हो सकती है, जबकि हाइपरथायरॉइड में चिड़चिड़ापन और चिंता बढ़ सकती है। आयुर्वेद इन लक्षणों के लिए मानसिक संतुलन लाने वाले जड़ी-बूटियों और ध्यान को अहम मानता है।थायरॉइड एक ऐसी समस्या है जो समय पर ध्यान न देने पर जीवनभर की चुनौती बन सकती है। एलोपैथिक उपचार में जहां लक्षणों पर काम किया जाता है, वहीं आयुर्वेद इसका मूल कारण खोजकर उसे ठीक करने का प्रयास करता है। संतुलित आहार, उचित दिनचर्या, जड़ी-बूटियों का प्रयोग और योग-प्राणायाम अपनाकर न केवल थायरॉइड विकार को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर की जा सकती है।

आयुर्वेद हमें यह सिखाता है कि शरीर को केवल दवा से नहीं, बल्कि सही जीवनशैली और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर स्वस्थ रखा जा सकता है। थायरॉइड जैसी आधुनिक बीमारियों का समाधान हमारे अपने प्राचीन ज्ञान में ही छिपा है—बस जरूरत है उसे अपनाने की।

संत नागरीदास जीः राधा-कृष्ण की भक्ति में रमे रसिक संत

संत नागरीदास जी का जीवन श्री राधा-कृष्ण की भक्ति का ऐसा अनुपम उदाहरण है, जो हर भक्त के हृदय को प्रेम और रस से सराबोर कर देता है। उन्होंने राजसी वैभव, सुख और ऐश्वर्य को ठोकर मारकर नंदनंदन श्रीकृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। वृंदावन की रसभूमि में राधा-कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए उन्होंने अपने जीवन को भक्ति की सुगंध से महका दिया। उनकी रचनाएँ और उनका जीवन आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए, इस रससिद्ध संत के जीवन और उनके भक्ति भरे कार्यों को सरल और आत्मीय शब्दों में जानें।

राजसी वैभव से भक्ति की राह तक

कृष्णगढ़ के राजकुमारः सावंत सिंह

संत नागरीदास जी का जन्म राजस्थान के इतिहासप्रसिद्ध कृष्णगढ़ राज्य में संवत् 1756 में पौष कृष्ण द्वादशी को हुआ। उनके पूर्वाश्रमी नाम सावंत सिंह था। उनके पिता, राजा राजसिंह, न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण के परम भक्त भी थे। उनके उदात्त चरित्र का प्रभाव बालक सावंत सिंह पर गहरा पड़ा। बचपन से ही सावंत सिंह में विलक्षण प्रतिभा और वीरता दिखाई देती थी। वे अपने कुलदेवता कल्याणराय और नृत्य गोपाल की मूर्तियों के प्रति विशेष अनुराग रखते थे। साधु-संतों का सान्निध्य उन्हें हृदय से प्रफुल्लित कर देता था।

युवावस्था में उनका विवाह भानगढ़ की राजकुमारी से हुआ, लेकिन गृहस्थी के सुख और राजमहल का वैभव उनके मन को कभी बाँध न सका। शिकार और अन्य राजसी शौक में उनकी रुचि धीरे-धीरे क्षीण होने लगी। उनका मन बार-बार वृंदावन की ओर खींचता था। वे कहते थेः

कव वृन्दावन धरनि में, चरन परेगे जाय।
लोटि घरि घरि सीस पर, कछु मुखहूँ में खाय।

उनके रोम-रोम में श्यामसुंदर का प्रेम बस गया था। वे कहते थे कि श्रीकृष्ण के नयनों से नयन मिलते ही उनका मन उनमें खो गया। अब उनके बिना न दिन कटता था, न रात, न खाने-पीने में रुचि बची थी। प्रेम की यह वेदना उनके हृदय को हर पल झकझोरती थी।

कृष्णगढ़ का गौरवशाली इतिहास

कृष्णगढ़ राज्य की स्थापना संवत् 1668 में जोधपुर नरेश उदयसिंह के पुत्र कृष्णसिंह ने की थी। यह राज्य दिल्ली की तत्कालीन मुगल सत्ता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था। मुगल बादशाह कृष्णगढ़ के राजाओं का विशेष सम्मान करते थे। इस राज्य के अधिकांश नरेश भगवद्भक्त और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। ऐसे भक्ति-भरे राजपरिवार में जन्म लेकर सावंत सिंह, जो बाद में संत नागरीदास बने, ने व्रज के रस का अनुपम आस्वादन किया।

भक्ति की राह में संन्यास

दिल्ली दरबार और भक्ति की प्यास

सावंत सिंह कभी-कभी दिल्ली दरबार में जाया करते थे, जहाँ उनकी मुलाकात बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं से होती थी। संवत् 1804 में दिल्ली यात्रा के दौरान बादशाह मुहम्मद शाह उनकी वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें विशेष सम्मान मिला। वहाँ उनकी मुलाकात घनानंद से हुई, जो बादशाह के निजी सचिव और एक रसिक कवि थे। घनानंद भी श्रीकृष्ण के परम भक्त थे, और यहीं से दोनों में गहरी मित्रता हो गई। यह मित्रता बाद में वृंदावन में और गहरी हुई।

लेकिन दिल्ली के वैभव और राजसी ठाठ-बाट सावंत सिंह के मन को कभी रास न आए। उनका चित्त सदा वृंदावन की ओर खींचता था। वे हर पल सोचते कि कब वे नंदनंदन की लीलाभूमि वृंदावन के दर्शन करेंगे।

यमुना तट पर भगवद् दर्शन की ललक

संवत् 1809 के आसपास, कमाऊँ के युद्ध से लौटते समय सावंत सिंह ने वृंदावन होते हुए कृष्णगढ़ लौटने का निर्णय लिया। यमुना तट पर पहुँचते-पहँचते रात हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा छा गया था, और नदी पार करने का कोई साधन नजर न आ रहा था। उधर, मंदिर में श्रीकृष्ण की आरती हो रही थी। सावंत सिंह का मन इतना आतुर हो उठा कि उन्होंने बिना देर किए यमुना की धारा में छलांग लगा दी। भगवान की कृपा से वे नदी पार कर गए और श्रीकृष्ण की आरती के दर्शन किए। इस घटना ने उनके जीवन को और गहराई से भक्ति की ओर मोड़ दिया।

राजपाट का त्याग

वृंदावन के रसिक संतों के सत्संग ने सावंत सिंह के मन को इतना मुग्ध कर दिया कि उन्होंने राजकार्य का त्याग करने का निश्चय कर लिया। उनकी अनुपस्थिति में उनके भाई बहादुरसिंह ने कृष्णगढ़ के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। सावंत सिंह ने मराठों की मदद से राज्य को पुनः अपने अधीन किया, लेकिन भाई के विश्वासघात ने उनके मन को गहरे तक आहत कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि राज्य और गृह-कलह सुख के लिए शूल के समान हैं। अंततः, उन्होंने अपने पुत्र सरदारसिंह को राजपाट सौंपकर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया।

वृंदावन में उनकी उपपत्नी वनीठनी, जिन्हें 'रसिकविहारिणी' के नाम से जाना जाता है, उनके साथ विरक्त भाव से रहीं। जब संतों को पता चला कि कृष्णगढ़ के राजा सावंत सिंह अब संत नागरीदास के रूप में वृंदावन में रह रहे हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मंदिरों में उनके भक्ति भरे पद गाए जाने लगे, और व्रज के कण-कण में उनकी रसिकता फैल गई।

वृंदावन में रसिकता का उत्कर्ष

भक्ति और रस की साधना

वृंदावन में संत नागरीदास जी ने अपने उपास्य देव भगवान नागरविहारी का मंदिर बनवाया और उनकी सेवा में लीन हो गए। उनका समय राधा-कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में बीतने लगा। वे रससिद्ध संत थे, जिन्होंने श्री राधा-कृष्ण के प्रकट और अप्रकट विहार-दर्शन को अपनी साधना का केंद्र बनाया। उनकी भक्ति में वल्लभ संप्रदाय के प्रति गहरी निष्ठा थी, और उन्होंने राधावल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों की भी प्रशंसा की। वे कहते थेः

परम पुष्टि रस जल अमित, उर्मी प्रेमावेस।
नागरि प्रगट आनन्दनिधि, वल्लभसुत विठलेस।

हितहरिवंश और हरिदास स्वामी जैसे महान संतों के भक्ति-सिद्धांतों से भी वे प्रभावित थे। उनकी गुरु-निष्ठा अनुपम थी। उनके गुरु रणछोड़ जी, जो गोपीनाथ जी के पौत्र थे, ने उन्हें भक्ति की गहराइयों में ले जाया। यात्राओं के दौरान वे अपने सेव्य 'नृत्यगोपाल' की मूर्ति साथ रखते थे, और युद्धों में भी श्रीकृष्ण की आराधना में लीन रहते थे।

घनानंद के साथ सत्संग

वृंदावन में संत नागरीदास जी की मित्रता घनानंद के साथ और गहरी हो गई। दोनों राधा-कृष्ण के प्रेम और रस के महान प्रेमी थे। जहाँ नागरीदास रससिद्ध संत थे, वहीं घनानंद वैराग्यसिद्ध रसिक थे। दोनों ने एक-दूसरे के सत्संग से भक्ति और रस की नई ऊँचाइयाँ छुईं। संत नागरीदास ने कभी वृंदावन का त्याग नहीं किया और यहीं राधा-कृष्ण की लीलाओं में डूबे रहे।

रचनाएँः भक्ति का अमृत

संत नागरीदास जी ने अपनी भक्ति और रसिकता को अपनी रचनाओं में उतारा। उनकी रचनाएँ राधा-कृष्ण की लीलाओं का सरस और आत्मीय चित्रण करती हैं। उनकी प्रमुख रचनाएँ हैंः मनोरथ मजरी, रसिक रत्नावली, विहार-चन्द्रिका, निकुज विलास, व्रजयात्रा, भक्तिसार, पारायणविधि प्रकाश, गोपीप्रेम प्रकाश और वनजन प्रशंसा।

इन रचनाओं में संत नागरीदास जी ने श्री राधा-कृष्ण की लीलाओं को इतने सरस और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया कि वे आज भी भक्तों के हृदय में रस घोलती हैं। उनकी रचनाएँ व्रज साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान रखती हैं।

नित्य लीला में प्रवेश

संवत् 1821 के आसपास संत नागरीदास जी ने इस नश्वर देह का त्याग कर श्री राधा-कृष्ण के नित्य लीला धाम में प्रवेश किया। उनका सम्पूर्ण जीवन भक्ति, प्रेम और रसिकता से परिपूर्ण था। वे एक उच्च कोटि के कवि, असाधारण महात्मा और आदर्श रसिक थे। वृंदावन में उनकी रसिकता आज भी कण-कण में बसी है। उनके पद मंदिरों में गाए जाते हैं, और उनकी रचनाएँ भक्तों को भक्ति के रस में डुबो देती हैं।

संत नागरीदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भगवान के चरणों में ही है। राजसी वैभव और सांसारिक सुखों को ठुकराकर उन्होंने श्रीकृष्ण की भक्ति को चुना, और अपने जीवन को रस और प्रेम से भर दिया। उनकी रचनाएँ और उनका जीवन आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोप से सियासी संग्राम

जेल से बाहर आईं केरल की नन, स्वागत में पहुंचे CPI से BJP तक के नेता

@ रिंकू विश्वकर्मा

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार केरल की दो नन को NIA अदालत से जमानत मिलने के बाद शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद जेल के बाहर का नज़ारा राजनीतिक एकता और टकराव दोनों का मिला-जुला रूप पेश कर रहा था। यहां उनके स्वागत में एक तरफ वाम दल के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, तो दूसरी ओर भाजपा के दिग्गज नेता भी।केरल से ताल्लुक रखने वाली नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस को बीते 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि वे तीन आदिवासी लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रही थीं। इस कार्रवाई के पीछे बजरंग दल के एक स्थानीय पदाधिकारी की शिकायत बताई जा रही है, जिसने इस मामले को तूल दे दिया।

अदालत का फैसला और शर्तें

बिलासपुर जिले की NIA अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद ननों समेत तीनों आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिहाई के लिए प्रति व्यक्ति 50 हज़ार रुपये का निजी मुचलका भरना होगा और सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा कराने होंगे। इसके साथ ही, बिना अनुमति वे देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (NIA कोर्ट) सिराजुद्दीन कुरैशी की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले में दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अगले दिन सुनाया गया।

3 लोगों की हुई गिरफ्तारी

मामले की शुरुआत 25 जुलाई को हुई, जब दुर्ग रेलवे स्टेशन पर शासकीय रेल पुलिस ने नन प्रीति मैरी, वंदना फ्रांसिस और नारायणपुर के एक युवक सुकमन मंडावी को हिरासत में लिया। आरोप था कि ये लोग नारायणपुर जिले के ओरछा क्षेत्र से तीन आदिवासी लड़कियों को केरल ले जाने की योजना बना रहे थे, जहां उनका जबरन धर्मांतरण कराया जाना था।पुलिस के मुताबिक, शिकायत बजरंग दल के एक स्थानीय पदाधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसके बाद स्टेशन पर हंगामा हुआ और जीआरपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया।

सिर्फ विवाद तक सीमित नहीं रहा मामला

गिरफ्तारी के बाद यह मामला सिर्फ एक कानूनी विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देखते-देखते यह राजनीतिक रंग लेने लगा। हिंदूवादी संगठनों ने इसे धर्मांतरण का सुनियोजित प्रयास बताया, वहीं विपक्षी दलों ने इसे निर्दोष लोगों को परेशान करने की कार्रवाई करार दिया।बजरंग दल ने आरोप लगाया कि नन और उनका सहयोगी आदिवासी लड़कियों को लालच देकर अपने साथ ले जा रहे थे। उनका दावा था कि यह मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन का मामला है। दूसरी तरफ, ननों के समर्थकों का कहना है कि वे सिर्फ शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लड़कियों को ले जा रही थीं, इसका धर्म परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था।

राजनीतिक गलियारों में हलचल

गिरफ्तारी के बाद मामला छत्तीसगढ़ से निकलकर दिल्ली और केरल तक पहुंच गया।CPI सांसद पी. संतोष कुमार और वरिष्ठ नेता बृंदा करात ने इस कार्रवाई की निंदा की। करात ने तो यहां तक कहा कि बजरंग दल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ननों के समर्थन में बयान जारी किए और इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया।केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर समेत कई नेताओं ने भी ननों को निर्दोष बताते हुए रिहाई की मांग की। यह बात कई लोगों के लिए चौंकाने वाली थी कि इस मुद्दे पर भाजपा और वाम दल दोनों एक सुर में दिखे।

जेल से रिहाई और स्वागत

शनिवार को जैसे ही ननों की रिहाई हुई, जेल के बाहर उनका स्वागत करने के लिए समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ में CPI के नेता भी थे और भाजपा के प्रतिनिधि भी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के नेता एक साथ खड़े होकर ननों का अभिनंदन कर रहे हैं। यह नज़ारा भारतीय राजनीति में शायद ही कभी देखने को मिलता है।

सामाजिक और धार्मिक बहस

इस मामले ने एक बार फिर देश में धर्म परिवर्तन और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बहस को तेज कर दिया है।समर्थकों का तर्क है कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की आज़ादी देता है।विरोधियों का कहना है कि आदिवासी और गरीब तबके के लोगों को आर्थिक और सामाजिक प्रलोभन देकर धर्म बदलवाना एक संगठित अपराध है, जिसे रोकना जरूरी है।

हालांकि ननों और अन्य आरोपियों को फिलहाल जमानत मिल गई है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और NIA की जांच जारी है। अदालत ने भी साफ कहा है कि जांच में सहयोग करना सभी आरोपियों की जिम्मेदारी होगी।राजनीतिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर यह मामला लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। एक तरफ इसे धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों से जोड़कर देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर इसे आदिवासी समाज की संस्कृति और पहचान पर हमले के रूप में भी पेश किया जा रहा है। ननों की गिरफ्तारी से लेकर उनकी रिहाई तक की कहानी सिर्फ एक कानूनी प्रकरण नहीं, बल्कि देश की मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का आईना है।

बीज मंत्र का अर्थ-ज्ञान नहीं है जरूरी

बीज मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं होता, यह दिव्यशक्ति का बोध कराने वाला होता है तथा दिव्यता होते हुए भी वाचक होता है। यह देवता का अंश होते हुए भी उसके स्वरूप का ज्ञान कराता है, बोध कराता है। सद्गुरु की कृपा से यदि साधक बीज मंत्र के अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर ले तो मंत्र योग संहिता के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति सहज हो जाती है। मंत्र के अर्थ ज्ञान से तात्पर्य यह है कि साधक गुरु कृपा से पहले यह जान ले कि जिस बीज मंत्र का वह जाप कर रहा है वह उसे कहां तक ले जा सकता है। इस ज्ञान के बिना साधक चाहे कितना ही जाप कर ले, सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जब सद्गुरु की कृपा और मंत्र शास्त्र के अध्ययन से अर्थ हृदय में धारण करके, साधक बीज मंत्र साधना करता है तो बीज मंत्र उसकी समस्त कामनाओं की निश्चित रूप से पूर्ति करते हैं।

बीज मंत्र की शक्ति अपार और अनंत होती है। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है कि जो इसके दायरे में नहीं आता। अर्थात 'सर्वे सर्वार्थ वाचकाः'। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब इसे किसी देवता विशेष के अनुष्ठान में प्रयोग किया जाता है तब यह अवश्य ही कुछ निश्चित अर्थों में उसके साथ जुड़ जाता है। बीज मंत्र के भावार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ एवं तत्वार्थ को गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है। बीज मंत्र को बीज गणित से भी तुलना की जा सकती है। जिस प्रकार बीज गणित में एक्स, वाई, जैड आदि अक्षरों को विभिन्न प्रकार की संख्याओं के प्रतीक रूप में निर्धारण कर दिया जाता है और परिणाम को उनके मान के द्वारा ही जान लिया जाता है, उसी तरह बीज मंत्र के अर्थ को और उसके गूढ़ संकेत को गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है।

बीज मंत्रों का एक गणित होता है और तदानुसार उसका अर्थ भी होता है। जब साधक इनका किसी तत्ववेत्ता गुरु के माध्यम से पाठ करता है तो उसे तदानुसार फल भी प्राप्त होता है। बीज मंत्रों को पूरे विश्व ने मान्यता प्रदान कर दी है तथा करोड़ों भाई-बहनों के तथ्यगत प्रमाण इसके साक्षी हैं। इस शुभ अवसर पर मंत्रवेत्ता परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में कोटि-काटि नमन।

केवल शिक्षा मात्र है आधुनिक विज्ञान

कोई भी वैज्ञानिक शरीर का कोई भाग नहीं बना सकता। चन्द्रमा, सूर्य, तारे बनाना तो दूर की बात है। भगवान शिव ने गणेश जी की गर्दन पर हाथी का सिर लगा दिया था। इसी प्रकार उन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा दिया था। आज का आधुनिक विज्ञान यह कार्य नहीं कर सकता। यह अधूरा विज्ञान है। डरमैटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, वायलॉजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री सब व्यर्थ है केवल दैवव्यपाश्रय ही सत्य है, दैवव्य अमृत है। आयुर्वेद के आठ अंग हैं उनमें से एक अंग दैवव्यपाश्रय है। इसे भूतविद्या भी कहते हैं तथा अलग-अलग नामों से जानते हैं। आधुनिक दवाइयां लगभग असफल हैं। एक बीमारी सही होती है तो सौ बीमारियां लग जाती हैं। यह आधुनिक शिक्षा अधूरा ज्ञान है। जब तक दैवव्यपाश्रय मां काली, भगवान भैरव और भगवान शिव को नहीं जानेंगे तब तक कोई ब्राह्मण और ज्योतिषाचार्य नहीं हो सकता। वह व्यक्ति विद्वान भी नहीं होता क्योंकि विद्वान का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जाने, परमात्मा को जाने। मां काली को जानने वाला ही ब्रह्मज्ञानी है। मां काली सौम्य, शीतल, सुन्दर व शक्तिशाली है। यह अद्भुत शक्तियों की स्वामिनी है और विज्ञान है।

दैवव्यपाश्रय में समस्त रोगों का समाधान

जब मैं अमेरिका गया तो वहां बड़े-बड़े डाक्टर कहने लगे कि हमारे यहां ऐसे असाध्य रोग हैं जो हमारी दवाइयों से जाते नहीं हैं। जैसे सोरायसिस है, इसके इलाज में 50 लाख डालख तक खर्च हो जाने पर भी यह रोग नहीं जाता। यूटीआई एक साल की बच्ची से लेकर सौ साल तक की स्त्री को है क्योंकि वहां के चिकित्सक दैवव्यपाश्रय को नहीं जानते। यूटीआई में कीटाणुओं का एक समूह है जो शरीर को काटता है। इसीलिए बहनें दुखी होती हैं। डाक्टर कहते हैं कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है, न कोई टैस्ट है। इस रोग से ग्रस्त महिलाओं से उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता क्योंकि उनका मूलाधार बंद हो जाता है। जैसे सांस बंद हो जाए। ऐसे में केवल दैवव्यपाश्रय जो भगवान शिव का दिया हुआ आलोक है, कार्य करता है। इसी के प्रारूप से मेरिकल वी वाश बनाया है जो एक मिनट में रोग को समाप्त कर देता है। रोती हुई स्त्री शांत हो जाती है। यह चार हजार रोगों को समाप्त करता है ।

यह न कोई दवाई है, न ड्रग है, न कोई साल्ट है,
केवल पवित्र नदियों का जल है।
दैवव्यपाश्रय साक्षात ब्रह्म
है, यह महाकाली है।

सियासी विरासत से सलाखों तक

बलात्कार केस में प्रज्वल रेवन्ना दोषी

@ मनीष पांडेय

कर्नाटक की सियासत में एक बड़ा नाम और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के परिवार का अहम चेहरा — प्रज्वल रेवन्ना — अब एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां सियासी ताकत, पारिवारिक रसूख और पद की चमक सब धुंधली पड़ चुकी है। महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार के संगीन मामले में विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है।

कोर्ट में टूटा सियासी वारिस का हौसला

जब शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो प्रज्वल रेवन्ना खुद को संभाल नहीं पाए। आंखें भर आईं, गला रुंध गया और वो कोर्ट में ही फूट-फूटकर रो पड़े। फैसले के बाद जब वो बाहर निकले, तो उनके चेहरे पर निराशा, आंखों में आंसू और कदमों में थकान साफ झलक रही थी। बाहर मौजूद लोगों ने बताया कि वे बिना किसी से कुछ कहे, चुपचाप निकल गए।अदालत ने फिलहाल सजा का ऐलान टालते हुए स्पष्ट किया कि फैसला अब तय हो चुका है, प्रज्वल रेवन्ना दोषी हैं। सजा का ऐलान शनिवार, 2 अगस्त को किया जाएगा।

14 महीने से जेल में, बेल की हर कोशिश नाकाम

पूर्व सांसद रेवन्ना पिछले 14 महीने से न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ एक नहीं बल्कि कई महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए — यौन शोषण, बलात्कार और अनुचित आचरण के। यह मामला तब तूल पकड़ गया जब सोशल मीडिया पर उनके कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गए। इन वीडियो ने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया और पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी।रेवन्ना के वकीलों ने बेल के लिए हर संभव कोशिश की। निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। लेकिन हर बार अदालतों ने यह कहते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं कि वह एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं और मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं।

26 गवाह, पुख्ता सबूत और मेडिकल रिपोर्ट

मामले की सुनवाई तेज रफ्तार से हुई। अदालत में 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पीड़िताओं के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और डिजिटल सबूतों ने इस केस को मजबूत किया। जज संतोष गजानन भट की अदालत ने साफ कहा कि प्रस्तुत सबूत और गवाहियों से यह साबित होता है कि रेवन्ना दोषी हैं।

14 महीने में ट्रायल हुआ पूरा

आमतौर पर इस तरह के संगीन मामलों में सुनवाई सालों तक खिंचती है। लेकिन इस केस में 14 महीने के भीतर ही ट्रायल पूरा कर लिया गया। यह अपने आप में एक मिसाल है कि संवेदनशील मामलों में अगर जांच और सुनवाई को प्राथमिकता दी जाए, तो न्याय जल्दी मिल सकता है।

देवेगौड़ा परिवार पर असर

रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के राजनीतिक परिवार के तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। उनका दोषी ठहराया जाना न केवल व्यक्तिगत, बल्कि पारिवारिक और राजनीतिक स्तर पर भी बड़ा झटका है। कर्नाटक की राजनीति में देवेगौड़ा परिवार का प्रभाव लंबे समय से कायम रहा है, लेकिन इस घटना ने उसकी छवि पर गहरा धब्बा छोड़ दिया है।मामले में फैसला आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

कुछ लोगों ने अदालत की तेजी की सराहना की, तो कुछ ने इसे राजनीति से जोड़कर देखा। हालांकि, पीड़ित पक्ष और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे "न्याय की दिशा में अहम कदम" बताया।अब सबकी निगाहें शनिवार पर टिकी हैं, जब अदालत रेवन्ना की सजा सुनाएगी।

यह देखना होगा कि उन्हें कितनी सजा मिलती है और क्या इसके बाद वह कोई कानूनी विकल्प अपनाते हैं। फिलहाल, कर्नाटक की राजनीति में यह मामला चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन

हरी-भरी रेल यात्रा की शुरुआत

भारत ने 26 जुलाई 2025 को अपनी पहली हाइड्रोजन-पावर्ड ट्रेन कोच का सफल टेस्ट किया। ये उपलब्धि भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा कदम है, जो न सिर्फ सस्ती और सुविधाजनक यात्रा देता है, बल्कि पर्यावरण को भी बचाता है। ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है, जो केवल पानी का वाष्प छोड़ती है, यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन! भारत के ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों के साथ ये कदम रेलवे को और सस्टेनेबल बनाएगा। इस लेख में हम इस नई तकनीक को, इसके फायदों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं को आसान हिंदी में समझेंगे।

हाइड्रोजन ट्रेन: ये है क्या चीज?

हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है। ये सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाता है, और इसका एकमात्र बाय-प्रोडक्ट है पानी का वाष्प। मतलब, कोई धुआं, कोई प्रदूषण! ये ट्रेन 1,200 हॉर्सपावर की ताकत के साथ दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है।

भारतीय रेलवे ने चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में इस कोच का टेस्ट किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे "फ्यूचर-रेडी और सस्टेनेबल भारत" की दिशा में बड़ा कदम बताया। ये ट्रेन खासकर उन रास्तों पर फायदेमंद है जहां इलेक्ट्रिक लाइनें बिछाना मुश्किल है, जैसे पहाड़ी या रिमोट इलाके।

इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है इसका जीरो कार्बन उत्सर्जन। डीजल ट्रेनें हर साल लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचातीं। साथ ही, ये ट्रेनें शांत होती हैं, यानी कम शोर और कम वाइब्रेशन, जो यात्रियों के लिए और आरामदायक अनुभव देता है।

'हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज': भारत का बड़ा प्लान

भारतीय रेलवे ने 'हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज' प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें हेरिटेज और पहाड़ी रास्तों पर चलेंगी। हर ट्रेन की लागत करीब 80 करोड़ रुपये और हर रूट के लिए ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत 70 करोड़ रुपये होगी। 2023-24 के बजट में इन ट्रेनों के लिए 2,800 करोड़ रुपये और हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 600 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

पहला पायलट प्रोजेक्ट जिंद-सोनीपत रूट (89 किमी) पर चल रहा है, जहां एक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (DEMU) को हाइड्रोजन फ्यूल सेल में बदला गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 111.83 करोड़ रुपये है। ये ट्रेन 110 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती है और 2,638 यात्रियों को ले जा सकती है। मार्च 2025 तक इस ट्रेन का पूरा टेस्ट हो जाएगा, और अगस्त 2025 तक इसे पूरी तरह रोलआउट करने की योजना है।

इसके अलावा, एक 8-कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन भी बन रही है, जो दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी। ये खास तौर पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल जैसे हेरिटेज और टूरिस्ट रूट्स के लिए होगी, जहां लोग नेचर की खूबसूरती का मज़ा ले सकेंगे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए।

पर्यावरण और इकोनॉमी: डबल फायदा

हाइड्रोजन ट्रेनें भारत के नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन (2030 तक रेलवे और 2070 तक देश) के लक्ष्य को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। एक हाइड्रोजन ट्रेन हर साल 400 कारों जितना कार्बन उत्सर्जन बचा सकती है। ये ट्रेनें डीजल की जगह लेगी, जिससे भारत की फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, ये लोकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी, जो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है।

हाइड्रोजन ट्रेनें उन रास्तों पर भी चल सकती हैं जहां इलेक्ट्रिक लाइनें नहीं हैं। इससे इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्च और समय बचेगा। उदाहरण के लिए, जर्मनी की Alstom Coradia iLint ट्रेन 1,000 किमी तक बिना रीफ्यूलिंग के चल सकती है और 20 मिनट में रीफ्यूल हो जाती है। भारत का प्रोटोटाइप भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है।

लेकिन, शुरुआती लागत अभी ज्यादा है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन और रीफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय और पैसा लगेगा। फिर भी, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और ज्यादा ट्रेनें आएंगी, लागत कम होगी। भारत की नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन) इस दिशा में बड़ा सपोर्ट दे रही है।

चुनौतियां: रास्ता आसान नहीं

हाइड्रोजन ट्रेनों का रास्ता इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अभी भारत में ज्यादातर हाइड्रोजन स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग से बनता है, जो ग्रे हाइड्रोजन कहलाता है और कार्बन उत्सर्जन करता है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलाइज़र चाहिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन बनाता है। लेकिन भारत में अभी ऐसे बड़े प्लांट्स की कमी है।

दूसरी चुनौती है रीफ्यूलिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। जिंद-सोनीपत रूट के लिए 430 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन प्रति दिन बनाने की सुविधा बन रही है। लेकिन पूरे देश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बड़ा टास्क है। इसके लिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) से सेफ्टी अप्रूवल्स भी चाहिए।

तीसरी बात, हाइड्रोजन ट्रेनें अभी डीजल ट्रेनों से महंगी हैं। लेकिन जैसे-जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, लागत कम होगी। फिर भी, शुरुआती निवेश और तकनीकी ऑप्टिमाइजेशन (जैसे ठंडे या गर्म मौसम में ज्यादा लोड के साथ चलना) में समय लगेगा। उदाहरण के लिए, कालका-शिमला रूट पर टेस्टिंग में पता चला कि ठंडे मौसम में 2,200 से ज्यादा यात्रियों के साथ ट्रेन को धीमा करना पड़ सकता है।

भविष्य: हाइड्रोजन ट्रेनों का सुनहरा दौर

भारत का हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट न सिर्फ रेलवे को बदलेगा, बल्कि टूरिज्म और इकोनॉमी को भी बूस्ट देगा। हेरिटेज रूट्स जैसे कालका-शिमला पर ये ट्रेनें टूरिस्ट्स को शांत और साफ यात्रा का अनुभव देंगी। साथ ही, भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल को भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये ट्रेनें पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बन रही हैं।

भारत अब जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जो हाइड्रोजन ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला रेल नेटवर्क बनाना है। इसके लिए रेलवे सोलर पावर, बायो-डीजल और इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे अन्य ग्रीन इनिशिएटिव्स पर भी काम कर रहा है।

हाइड्रोजन ट्रेनें भारत के ग्रीन मोबिलिटी मिशन का हिस्सा हैं। 2024 में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भूटान के प्रधानमंत्री को हाइड्रोजन से चलने वाली बस दिखाई थी, जो इंडियन ऑयल ने बनाई थी।

ऑपरेशन सिंदूर: भारत का सर्जिकल स्ट्राइक और पहलगाम हमले का जवाब

पहलगाम आतंकी हमला: क्या हुआ था?

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट थे, साथ ही एक नेपाली नागरिक, एक क्रिश्चियन टूरिस्ट और एक स्थानीय मुस्लिम भी शामिल था। हमलावरों ने बैसारन वैली में टूरिस्ट्स को टारगेट किया, जहां उन्होंने पहले पुरुषों को महिलाओं से अलग किया और फिर गैर-मुस्लिम लोगों को गोली मार दी। यह हमला 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत में सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है।

हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) नामक संगठन ने ली, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक हिस्सा है। TRF ने दावा किया कि यह हमला कश्मीर में गैर-स्थानीय लोगों के बसने के खिलाफ था। हालांकि, बाद में उन्होंने इस जिम्मेदारी से इनकार कर दिया, जिसे विशेषज्ञों ने पब्लिक ओपिनियन में बैकफायर से बचने की कोशिश बताया।

भारत ने इस हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ा और इसके जवाब में कई कदम उठाए। सरकार ने इंडस वॉटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए, अटारी बॉर्डर बंद किया और पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र बंद कर दिया।

ऑपरेशन सिंदूर: भारत का करारा जवाब

7 मई 2025 को भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इन ठिकानों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के कैंप शामिल थे। भारत ने दावा किया कि इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जबकि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक ठिकाने को टारगेट नहीं किया गया।

ऑपरेशन का नाम 'सिंदूर' इसलिए चुना गया क्योंकि यह पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की विधवाओं के दुख को दर्शाता है। भारत ने इसे एक "मेजर्ड और नॉन-एस्केलेटरी" (सीमित और गैर-उत्तेजक) ऑपरेशन बताया, जिसका मकसद सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना था।

पाकिस्तान ने इन हमलों को "युद्ध की कार्रवाई" करार दिया और दावा किया कि 31 लोग मारे गए, जिनमें सिविलियन भी शामिल थे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसके चलते भारत में 12 सिविलियन्स और एक सैनिक की मौत हुई।

भारत-पाकिस्तान तनाव: क्या थी वजह?

ऑपरेशन सिंदूर ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने पांच भारतीय विमानों को मार गिराया, जिसमें तीन राफेल जेट शामिल थे। हालांकि, भारत ने इन दावों का खंडन नहीं किया, लेकिन यह कहा कि सभी भारतीय पायलट सुरक्षित घर लौट आए।

पाकिस्तान ने भारत के हमलों के जवाब में जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। भारतीय सेना ने इन हमलों को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

10 मई को दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स (DGMO) के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद 12 मई को एक सीजफायर समझौता हुआ। इस समझौते में दोनों देशों ने गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में हराया है और ऑपरेशन सिंदूर ने इसे फिर साबित किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति है और पाकिस्तान को अपनी आतंकी गतिविधियां बंद करनी होंगी।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: दुनिया ने क्या कहा?

पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, कतर, सिंगापुर और सऊदी अरब जैसे देशों ने हमले की निंदा की और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि उन्होंने सीजफायर में मध्यस्थता की, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने को कहा, जबकि चीन ने भारत के हमलों को "खेदजनक" बताया।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को सबूत पेश किए कि पहलगाम हमला पाकिस्तान प्रायोजित था। भारत ने यह भी मांग की कि TRF को आतंकी संगठन घोषित किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की राह

ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने वादा किया था कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा, लेकिन वह अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए अपनी सैन्य ताकत और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया। पहलगाम हमले से कश्मीर में टूरिज्म पर बुरा असर पड़ा। हमले के बाद कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स बंद कर दिए गए और 2025 में टूरिस्ट्स की संख्या 2024 की तुलना में 50% से ज्यादा कम हो गई। इसके अलावा, एक पाकिस्तानी महिला को इस हमले से जोड़ा गया और उसे भारत से डिपोर्ट कर दिया गया। हालांकि, इस मामले में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

निष्कर्ष

ऑपरेशन सिंदूर भारत के आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख का प्रतीक है। यह ऑपरेशन न केवल पहलगाम हमले का जवाब था, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि, इस ऑपरेशन ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा दिया, जिससे दोनों देशों के लिए शांति और कूटनीति की राह चुनना जरूरी हो गया है।

आगे की राह में भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करना होगा, साथ ही कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठाने होंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तनाव भविष्य में और बढ़ेगा या दोनों देश शांति की दिशा में काम करेंगे?

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

माँ का जवान चेहरा

मेरे बचपन की ढेरों स्मृतियों में हैं
ढेर सारी बातें, पुराने दोस्त

नन्ही शैतानियाँ, टीचर की डाँट
और न जाने क्या-क्या

मेरी बचपन की स्मृतियों में है
माँ की लोरी, प्यार भरी झिड़की

पिता का थैला, थैले-से निकलता बहुत कुछ
मेरी बचपन की स्मृतियों में है

पिता का जाना, माँ की तन्हाई
छोटी बहन का मासूम चेहरा

लेकिन न जाने क्यूँ मेरी बचपन की
इन ढेरों स्मृतियों में नहीं दिखता

कभी माँ का जवान चेहरा
उनकी माथे की बिंदिया

उनके भीतर की उदासी और सूनापन
माँ मुझे दिखी है हमेशा वैसी ही

जैसी होती है माँ
सफ़ेद बाल और धुँधली आँखें

बच्चों की चिंता में डूबी
ज़रा सी देर हो जाने पर रास्ता निहारती

मैं कोशिश करती हूँ कल्पना करने की
कि जब पिता के साथ होती होगी माँ

तो कैसे चहकती होगी, कैसे रूठती होगी
जैसे रूठती हूँ मैं आज अपने प्रेमी से

माँ रूठती होगी तो मनाते होंगे पिता उन्हें
कैसे चहक कर ज़िद करती होगी पिता से

किसी बेहद पसंदीदा चीज़ के लिए
जब होती होगी उदास तो

पिता के कंधों पर निढाल माँ कैसी दिखती होगी
याद करती हूँ तो बस याद आती है

हम उदास बच्चों को अपने आँचल में सहेजती माँ
माँ मेरी ज़िंदगी का अहम् हिस्सा है या आदत

नहीं समझ पाती मैं
मैं चाहती हूँ माँ को अपनी आदत हो जाने से पहले

माँ को माँ होने से पहले देखना सिर्फ़ एक बार!

ज्योति चावला
इस सदी में सामने आईं हिंदी कवयित्री और कथाकार

झूठ बोलती लड़कियाँ

न जाने क्यों झूठ बोलती लड़कियाँ
मुझे अच्छी लगती हैं

झूठ बोलती लड़कियों का झूठ बोलना
न जाने क्यों मुझे अच्छा लगता है

अच्छा लगता है उनका झूठ बोलकर
कुछ पल चुरा लेना सारे दायरों से

इन चुने हुए कुछ पलों में वे
फड़फड़ा आती हैं अपने पंखों को

कुछ देर के लिए खुली हवा में और
सुते हुए नथुनों में भर कर हवा के ताज़े झोंके

वे फिर लौट आती हैं अपने पहले से तय दायरों में
झूठ बोलती लड़कियाँ बोलती हैं छोटे-छोटे झूठ

और अपने जीवन के चुभते-नुकीले सचों को
ताक पर रख देती हैं कुछ देर के लिए

वे छूती हैं झूठ से बनी इस छोटी-सी दुनिया को
अपनी कोमल उँगलियों के कोमल पोरों से और

उसकी सिहरन से भीतर तक झूम जाती हैं
झूठ बोलती लड़कियाँ बोलती हैं झूठ और

उन पलों में अक्सर कहती हैं
दुनिया ख़ूबसूरत है, इसे ऐसा ही होना चाहिए।

कनाडा की धरती के नीचे खजाना

ब्रिटिश कोलंबिया में मिला तांबा और सोना, वैश्विक खनन जगत में हलचल

@ रिंकू विश्वकर्मा

वैंकूवर/ब्रिटिश कोलंबिया। उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया की ठंडी, कठिन और अब तक कम खोजी गई ज़मीन के भीतर एक बार फिर से सोना और तांबा चमक उठा है। सतह से महज़ 59 फीट नीचे मिले इस खजाने ने न केवल कनाडा के खनन उद्योग में नई उम्मीद जगा दी है, बल्कि दुनिया भर के खनन निवेशकों की नज़रें भी इस ओर टिक गई हैं। यह खोज "ऑरोरा" नामक स्थल पर हुई है, जहां 2024 से पहले कभी ड्रिलिंग नहीं की गई थी। अब पहली बार यहां की गई खोज ने उम्मीद से कहीं बेहतर नतीजे दिए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह खोज आने वाले वर्षों में कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ वैश्विक खनन क्षेत्र में उसकी पकड़ को और मजबूत कर सकती है।

गोल्डन ट्रायंगल का अनछुआ कोना

यह खोज अमार्क रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के तहत हुई है, जो उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया के गोल्डन ट्रायंगल के किनारे स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल अपने समृद्ध खनिज भंडार और भूवैज्ञानिक विविधता के लिए मशहूर है, लेकिन यहां की कठिन भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों ने दशकों तक बड़े पैमाने पर रिसर्च को रोके रखा।अब, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी उन्नति ने मौसमी ड्रिलिंग के नए रास्ते खोल दिए हैं। यही वजह है कि ऑरोरा साइट की खोज सिर्फ एक स्थानीय सफलता नहीं, बल्कि खनन के क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है।

सतह के करीब मिला उच्च गुणवत्ता वाला खनिज

इस तांबा-सोना भंडार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सतह से बेहद कम गहराई पर स्थित है। ड्रिलिंग के दौरान JP24057 नामक छेद में सतह से 59 फीट की गहराई पर औसतन 1.24 ग्राम प्रति टन सोना और 0.38 प्रतिशत तांबा मिला। इतनी कम गहराई पर इतने अच्छे ग्रेड का खनिज मिलना वैश्विक खनन उद्योग में दुर्लभ है।यही नहीं, इसी स्थान पर 190 फीट की गहराई में ड्रिलिंग करने पर और भी बेहतर परिणाम सामने आए 1.97 ग्राम प्रति टन सोना और 0.49 प्रतिशत तांबा। यह संकेत देता है कि सतह के नीचे परत दर परत उच्च गुणवत्ता वाला खनिज मौजूद है।

रणनीतिक दृष्टि से अहम

ऑरोरा साइट उत्तरी टूडोगोन ज्वालामुखीय चाप के किनारे स्थित है। इसके आसपास पहले से मौजूद सड़कें, ऊर्जा आपूर्ति और खनन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा इसकी रणनीतिक अहमियत को और बढ़ाते हैं। इससे खनन लागत कम होती है और उत्पादन शुरू करने में समय भी बचता है।साथ ही, यह खोज ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक बाजार में तांबे की मांग तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और डेटा सेंटर्स के विस्तार के कारण 2040 तक तांबे की मांग दोगुनी हो सकती है।

तांबा क्यों है भविष्य की धड़कन?

तांबा आधुनिक तकनीक का एक अहम हिस्सा है खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों में। एक इलेक्ट्रिक कार में पारंपरिक गैसोलीन कार की तुलना में करीब तीन गुना ज्यादा तांबे की जरूरत होती है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हाई-टेक डेटा सेंटर के निर्माण में भी तांबे की खपत तेजी से बढ़ रही है। दूसरी ओर, मौजूदा वैश्विक पोर्फिरी खदानों में खनिज की गुणवत्ता (हेड ग्रेड) लगातार घट रही है। ऐसे में ब्रिटिश कोलंबिया जैसे नए और उच्च ग्रेड वाले भंडार वैश्विक आपूर्ति के लिए बेहद अहम हो जाते हैं।

वैश्विक निवेशकों की नजर

खनन उद्योग के जानकार मानते हैं कि इस खोज का समय बिल्कुल सही है। एक ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत ऊंचाई पर है, दूसरी ओर ऊर्जा संक्रमण और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग ने तांबे को "रेड गोल्ड" का दर्जा दे दिया है।ऑरोरा का शुरुआती डेटा निवेशकों को आकर्षित कर रहा है क्योंकि यह सतह से बेहद करीब है, जिससे खनन लागत घटेगी। शुरुआती ड्रिलिंग में ही मजबूत ग्रेड मिला है। आसपास बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है। भौगोलिक स्थिति खनन और निर्यात के लिए अनुकूल है।

भविष्य की तस्वीर अहम भूमिका निभा सकती है

अभी इस खोज की पूरी क्षमता का अंदाजा लगाना जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि ड्रिलिंग और सैंपलिंग का काम जारी है। लेकिन शुरुआती संकेत यह दर्शाते हैं कि ऑरोरा आने वाले वर्षों में कनाडा के सबसे अहम तांबा-सोना प्रोजेक्ट्स में से एक बन सकता है।अगर आगे के परिणाम भी इसी स्तर के रहे, तो यह साइट न केवल कनाडा, बल्कि वैश्विक खनन परिदृश्य में अहम भूमिका निभा सकती है।

कनाडा की अर्थव्यवस्था को नया सहारा

कनाडा पहले से ही खनिज निर्यात में एक बड़ी ताकत है, लेकिन ऑरोरा जैसी खोजें उसे अगले दशक में और मजबूत स्थिति में ला सकती हैं। इससे न केवल निवेश और रोजगार बढ़ेंगे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कनाडा की खनन प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।ऑरोरा की यह खोज सिर्फ एक खनन सफलता नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि कनाडा के अनछुए इलाकों में अब भी ऐसे खजाने छिपे हैं जो दुनिया की ऊर्जा और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

रेंगमा जंगल रिजर्व में असम की बड़ी बेदखली ड्राइव

पर्यावरण और मानवाधिकारों का टकराव

असम सरकार ने रेंगमा जंगल रिजर्व में 10,000 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए अगस्त 2025 में एक बड़ी बेदखली ड्राइव शुरू की। यह ड्राइव जैव विविधता को बचाने के लिए है, लेकिन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह मुद्दा भारत के पूर्वोत्तर में, खासकर असम में, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों के बीच तनाव को दिखाता है। असम के लोग इस ड्राइव के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं।

रेंगमा जंगल रिजर्व: प्रकृति का खजाना

रेंगमा जंगल रिजर्व असम के गोलाघाट जिले में, असम-नागालैंड सीमा के पास, उरियामघाट इलाके में है। यह 13,921 हेक्टेयर में फैला एक संरक्षित जंगल है, जो अपनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। इस जंगल में कई दुर्लभ पेड़-पौधे और जानवर हैं, जो इसे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, इस जंगल में अतिक्रमण बढ़ गया है। लोग यहाँ बस्तियाँ बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और जंगल को नुकसान पहुँचा रहे हैं।

असम सरकार का कहना है कि रेंगमा जंगल में लगभग 11,000 बीघा (लगभग 3,600 एकड़) जमीन पर अवैध कब्जा है। इन अतिक्रमणों ने जंगल की जैव विविधता को खतरे में डाल दिया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल का कटना और बस्तियों का बनना वन्यजीवों के घर और पानी के स्रोतों को नष्ट कर रहा है। इसलिए, सरकार ने इस जंगल को बचाने के लिए यह बेदखली ड्राइव शुरू की। गोलाघाट के डिप्टी कमिश्नर दिगंता कलिता ने कहा, "यह ड्राइव जंगल की रक्षा के लिए है, न कि किसी समुदाय को टारगेट करने के लिए।"

लेकिन यह ड्राइव इतनी आसान नहीं है। जंगल को बचाने की कोशिश में, हजारों परिवारों का घर उजड़ रहा है। यह हमें एक सवाल पर लाता हैः क्या पर्यावरण की रक्षा और लोगों के अधिकारों को एक साथ बचाया जा सकता है?

बेदखली ड्राइव का सच: क्या और कैसे?

यह बेदखली ड्राइव 29 जुलाई 2025 को शुरू हुई और इसका पहला चरण 2 अगस्त 2025 को खत्म हुआ। इस ड्राइव में 2,000 से ज्यादा असम पुलिस और 500 वन विभाग के कर्मचारी शामिल थे। 150 से ज्यादा बुलडोजर और एक्सकेवेटर का इस्तेमाल हुआ। पहले दिन, बिद्यापुर बाजार में 120 अवैध ढांचे तोड़े गए और 4.2 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई। पूरे चरण में, 8,900 बीघा जमीन और 4,000 से ज्यादा ढांचे साफ किए गए।

सरकार का कहना है कि यह ड्राइव असम वन संरक्षण अधिनियम, 1891 के तहत हो रही है। 2022 में गौहाटी हाई कोर्ट ने भी सरकार को जंगल में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। अधिकारियों ने पहले सर्वे किए, नोटिस दिए, और फिर ड्राइव शुरू की। गोलाघाट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुलक महंता ने कहा, "हमने सारी

कानूनी प्रक्रिया फॉलो की है ताकि यह ड्राइव शांतिपूर्ण हो।"

लेकिन इस ड्राइव ने कई सवाल खड़े किए हैं। जिन लोगों को हटाया गया, उनमें से ज्यादातर मिया मुस्लिम (बंगाली मूल के असमिया मुस्लिम) हैं, जो दशकों से यहाँ रह रहे हैं। कई लोग खेती और छोटे-मोटे बिजनेस करते हैं। एक विस्थापित व्यक्ति, रहीमुद्दीन अली, ने कहा, "मैंने अपनी जिंदगी की कमाई से घर बनाया था। अब हमें नहीं पता कि कहाँ जाएँ।" यह सवाल उठता है कि क्या सरकार इन लोगों के लिए कोई पुनर्वास योजना बना रही है?

मानवाधिकारों का सवाल: क्या हो रहा गलत?

इस बेदखली ड्राइव की सबसे बड़ी आलोचना मानवाधिकारों को लेकर है। इस ड्राइव से लगभग 1,500 से 2,000 परिवार विस्थापित हुए हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के हैं। विपक्षी दलों जैसे AIUDF और कांग्रेस ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि यह ड्राइव एक खास समुदाय को टारगेट कर रही है और इसे पर्यावरण संरक्षण का बहाना बनाया जा रहा है।

कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इस ड्राइव की आलोचना की है। उनका कहना है कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है, उन्हें पहले बिजली, पानी (जल जीवन मिशन), और PMAY-G के तहत घर जैसी सुविधाएँ दी गई थीं। अगर ये लोग अवैध थे, तो सरकार ने इन्हें ये सुविधाएँ क्यों दीं? कुछ लोग दावा करते हैं कि 1978-79 में जनता पार्टी और 1985 में AGP सरकार ने इन लोगों को यहाँ बसाया था ताकि असम-नागालैंड सीमा की रक्षा हो।

विस्थापित परिवारों का कहना है कि उनके पास पुनर्वास का कोई प्लान नहीं है। मधुपुर नंबर 2 में एक मस्जिद को तोड़े जाने की घटना ने लोगों को भावनात्मक रूप से आहत किया। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, "यह मस्जिद 1970 में बनी थी। इसे तोड़ना हमारे लिए बहुत दुखद है।" सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने गौहाटी हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल करने की योजना बनाई है, जिसमें वे अस्थायी रोक और विस्थापितों के लिए मुआवजे की मांग करेंगे।

पर्यावरण बनाम लोग: कौन सही, कौन गलत?

रेंगमा जंगल रिजर्व की बेदखली ड्राइव पर्यावरण और मानवाधिकारों के बीच एक जटिल टकराव को दिखाती है। एक तरफ, सरकार का कहना है कि यह ड्राइव जंगल और उसकी जैव विविधता को बचाने के लिए जरूरी है। रेंगमा जंगल में कई लोग सुपारी की खेती कर रहे हैं, जिसे "बेटल माफिया" से जोड़ा जा रहा है। यह खेती जंगल को नुकसान पहुँचा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "हमारा लक्ष्य जंगल को बचाना और असम की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना है।"

दूसरी तरफ, मानवाधिकार संगठन और विपक्षी दल कहते हैं कि यह ड्राइव एक खास समुदाय को टारगेट कर रही है। वे इसे "डेमोग्राफिक इनवेजन" रोकने का बहाना बताते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या पर्यावरण की रक्षा के नाम पर हजारों लोगों को बेघर करना सही है? क्या सरकार इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक जगह या पुनर्वास योजना नहीं बना सकती थी?

रेंगमा नगा समुदाय ने इस ड्राइव का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह जंगल उनके पूर्वजों की जमीन है और अतिक्रमण ने उनकी सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुँचाया है। ARWO ने मुख्यमंत्री सरमा की तारीफ की और कहा कि यह ड्राइव स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी। लेकिन यह भी सच है कि सभी विस्थापित लोग "अवैध" नहीं हैं। कुछ के पास फॉरेस्ट राइट्स कमेटी (FRC) सर्टिफिकेट हैं, जो उन्हें जंगल में रहने का अधिकार देते हैं।

आगे का रास्ता: क्या है समाधान?

यह बेदखली ड्राइव असम में जमीन और पहचान की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन गई है। सरकार का कहना है कि यह ड्राइव और चरणों में चलेगी, जिसमें नंबोर साउथ रिजर्व फॉरेस्ट जैसे इलाके भी शामिल होंगे। लेकिन इस ड्राइव के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं।

पुनर्वास एक बड़ा सवाल है। सरकार ने अभी तक विस्थापित परिवारों के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं बताई। कुछ लोग अपने मूल जिलों जैसे नागांव, मोरीगांव, या बारपेटा लौट रहे हैं, लेकिन उनके पास वहाँ भी संसाधन कम हैं। पड़ोसी राज्य जैसे नागालैंड और मेघालय ने अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि विस्थापित लोग उनके यहाँ न आएँ।

पर्यावरण विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि सरकार को जंगल की रक्षा और लोगों के पुनर्वास के बीच संतुलन बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, विस्थापित लोगों को जंगल के बाहर वैकल्पिक जमीन दी जा सकती है। साथ ही, जंगल की रक्षा के लिए सख्त निगरानी और पुनर्जनन प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं। असम के स्थानीय BJP MLA बिस्वजीत फूकन ने कहा, "रेंगमा जंगल को इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है, जिससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा हो।"

एक जटिल चुनौती

रेंगमा जंगल रिजर्व की बेदखली ड्राइव असम के सामने एक जटिल चुनौती है। यह पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, और सांस्कृतिक पहचान के बीच टकराव को दिखाती है। सरकार का इरादा जंगल को बचाने का है, लेकिन इस प्रक्रिया में हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। यह ड्राइव असम की जमीन और पहचान की राजनीति को और गहरा सकती है।

इस मुद्दे का समाधान आसान नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास की ठोस योजना बनाए। साथ ही, जंगल की रक्षा के लिए दीर्घकालिक उपाय किए जाएँ, जैसे अवैध कटाई पर रोक और जंगल की निगरानी। असम के लोग चाहते हैं कि उनका पर्यावरण सुरक्षित रहे, लेकिन यह भी जरूरी है कि किसी के अधिकारों का हनन न हो। क्या असम इस चुनौती से निपट पाएगा? यह समय बताएगा।

अमेरिका का भारत पर 25% टैरिफ: क्या होगा असर?

7 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत के सामानों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। यह फैसला भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के कारण लिया गया है। इससे भारत के टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल जैसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। यह मुद्दा भारतीयों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यह हमारी इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड में भारत की रणनीतिक आजादी को प्रभावित कर सकता है।

1. टैरिफ का बैकग्राउंड: क्यों और कैसे?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 30 जुलाई 2025 को ऐलान किया कि भारत के सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगेगा। इसके अलावा, भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए एक अतिरिक्त "पेनल्टी" भी होगी, जिसका ब्योरा अभी साफ नहीं है। ट्रम्प का कहना है कि भारत के हाई टैरिफ और "नॉन-मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स" अमेरिकी सामानों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। इसके साथ ही, भारत का रूस के साथ इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशन भी अमेरिका को खटक रहा है, खासकर यूक्रेन युद्ध के समय।

2024 में भारत ने अमेरिका को 86.5 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि अमेरिका से 45.3 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया। इससे भारत को 41.18 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस मिला। अमेरिका इसे "अनसस्टेनेबल" मानता है और इसे बैलेंस करने के लिए टैरिफ का सहारा लिया है। ट्रम्प ने अपने Truth Social प्लेटफॉर्म पर कहा, "भारत हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनके टैरिफ बहुत हाई हैं, और वे रूस से बहुत सारा तेल और सैन्य उपकरण खरीदते हैं, जो यूक्रेन युद्ध के समय ठीक नहीं है।"

यह टैरिफ केवल इकोनॉमिक नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल मूव भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहता है। भारत का कहना है कि वह सस्ता तेल खरीदकर अपनी जनता को राहत देता है।

2. कौन से सेक्टर्स पर पड़ेगा असर?

यह टैरिफ भारत के कई बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स को हिट करेगा। इनमें टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स और ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। आइए इनका डिटेल में जायजा लें:

टेक्सटाइल्स और अपैरल: भारत अमेरिका को होम लिनन्स, फुटवेयर और कपड़े एक्सपोर्ट करता है, जो Walmart और Gap जैसे ब्रैंड्स को सप्लाई करते हैं। 25% टैरिफ से ये प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिससे वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को फायदा हो सकता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कहा कि यह "कड़ा चैलेंज" है।

फार्मास्यूटिकल्स: भारत अमेरिका को 50% जेनेरिक दवाइयां सप्लाई करता है। 2022 में भारतीय जेनेरिक दवाओं ने अमेरिका को 220 बिलियन डॉलर की बचत कराई थी। टैरिफ से दवाइयां महंगी हो सकती हैं, जिससे अमेरिकी हेल्थकेयर कॉस्ट बढ़ेगा और भारत में फार्मा कंपनियों के प्रॉफिट और R&D पर असर पड़ेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स: भारत हाल ही में अमेरिका को iPhone का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना है। Apple ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन टैरिफ से यह प्लान प्रभावित हो सकता है।

जेम्स और ज्वेलरी: अमेरिका भारत के ज्वेलरी ट्रेड का 30% हिस्सा है। टैरिफ से इस सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है।

ऑटो पार्ट्स और स्टील: ऑटोमोबाइल और स्टील सेक्टर्स भी प्रभावित होंगे। 2018-19 में ट्रम्प के मेटल टैरिफ से भारत के स्टील एक्सपोर्ट में 9% की कमी आई थी।

एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि टैरिफ से भारत के 10% एक्सपोर्ट्स पर तुरंत असर पड़ेगा, और लंबे समय में सप्लाई चेन शिफ्ट हो सकती है। इससे भारत की GDP ग्रोथ 0.2-0.5% तक कम हो सकती है।

3. भारत का जवाब: रिटेलिएट या नेगोशिएट?

भारत सरकार ने टैरिफ के जवाब में सतर्क रुख अपनाया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि वह "नेशनल इंटरेस्ट" को प्रोटेक्ट करेगी और स्मॉल बिजनेसेज और किसानों को सपोर्ट करेगी। भारत ने अभी तक रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने से बचा है और डिप्लोमैटिक नेगोशिएशन्स पर फोकस कर रहा है।

नेगोशिएशन्सः भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं। अगस्त 25 को एक अमेरिकी ट्रेड डेलिगेशन भारत आएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फाइनल टैरिफ रेट 15-20% तक कम हो सकता है, अगर कुछ सेक्टर्स के लिए एक्सेम्पशन्स मिल जाएं।

डायवर्सिफिकेशन: भारत अब यूरोपियन यूनियन, ASEAN, और अफ्रीकन मार्केट्स के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स पर काम कर रहा है। यह अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करने की स्ट्रैटेजी है।

रूस के साथ रिलेशन: भारत ने रूस से तेल और डिफेंस इम्पोर्ट्स को डिफेंड किया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "हम 40 देशों से तेल इम्पोर्ट करते हैं। सस्ता तेल खरीदना हमारी जनता के लिए जरूरी है।"

WTO ऑप्शन्स: भारत के पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) के जरिए रिटेलिएट करने का अधिकार है। पहले भी भारत ने अमेरिकी गुड्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स की नोटिफिकेशन दी थी, लेकिन अभी तक इन्हें लागू नहीं किया।

कुछ इंडस्ट्री लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कांग्रेस, ने इस टैरिफ को भारत की फॉरेन पॉलिसी की "फेल्योर" बताया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रम्प की दोस्ती के बावजूद भारत को नुकसान हुआ।

4. जियोपॉलिटिकल एंगल: रूस, BRICS, और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी

यह टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल इश्यू भी है। अमेरिका भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए दबाव डाल रहा है। भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल और 60% डिफेंस इक्विपमेंट इम्पोर्ट करता है। ट्रम्प ने कहा कि भारत और चीन, रूस के सबसे बड़े एनर्जी बायर्स हैं, और यह यूक्रेन युद्ध के समय "अच्छा नहीं" है।

रूस के साथ टाईज: भारत ने यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल स्टांस लिया है और रूस के साथ अपने हिस्टोरिकल रिलेशन्स को डिफेंड किया है। भारत का कहना है कि वह सस्ते तेल से अपनी जनता को फायदा पहुंचाता है।

BRICS और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी: भारत BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका) का हिस्सा है, जो ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। लेकिन भारत ने रूस और चीन के साथ एंटी-वेस्टर्न ब्लॉक बनाने से इनकार किया है। भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बैलेंस करता है, जिसमें अमेरिका, रूस, और चीन के साथ अलग-अलग डोमेन्स में रिलेशन्स शामिल हैं।

अमेरिका-पाकिस्तान डील: अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक एनर्जी पार्टनरशिप की है, जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि, यह डायरेक्ट गैस ट्रेड नहीं है, लेकिन रीजनल ट्रेड और सिक्योरिटी पर इसका असर हो सकता है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह टैरिफ भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए प्रेशराइज करने की स्ट्रैटेजी है, लेकिन भारत अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं करेगा।

5. इकोनॉमिक और ग्लोबल इम्पैक्ट

टैरिफ का असर दोनों देशों पर पड़ेगा। भारत में इंडस्ट्रीज और जॉब्स पर खतरा है, जबकि अमेरिका में कंज्यूमर्स को हायर प्राइसेज का सामना करना पड़ेगा।

भारत पर असर: टैरिफ से भारत के एक्सपोर्ट्स में 10-20% की कमी आ सकती है, जिससे GDP ग्रोथ 0.3-0.5% तक कम हो सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर में 200,000 जॉब्स का रिस्क है। रुपये की वैल्यू भी कमजोर हो रही है।

अमेरिका पर असर: अमेरिकी कंज्यूमर्स को जेनेरिक दवाइयां, टेक्सटाइल्स, और ज्वेलरी महंगी मिलेंगी। इससे हेल्थकेयर कॉस्ट्स और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। कुछ अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो सकता है, लेकिन यह शॉर्ट-टर्म होगा।

ग्लोबल ट्रेड: टैरिफ से ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो सकती हैं। वियतनाम, मेक्सिको, और बांग्लादेश जैसे देश भारत की जगह ले सकते हैं। भारत अब नए मार्केट्स की तलाश में है।

मार्केट रिएक्शन: टैरिफ की खबर से भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट आई और रुपया कमजोर हुआ। टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, और फार्मा सेक्टर्स के शेयर्स डाउन हुए।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की डोमेस्टिक डिमांड-ड्रिवन इकोनॉमी इस शॉक को अब्सॉर्ब कर सकती है। सरकार आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव्स (PLI) जैसी स्कीम्स के जरिए इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है।

आगे क्या?

यह टैरिफ भारत और अमेरिका के रिलेशन्स के लिए एक बड़ा टेस्ट है। भारत को अब स्मार्ट डिप्लोमेसी और डायवर्सिफिकेशन की जरूरत है। ट्रेड टॉक्स में कुछ सेक्टर्स के लिए एक्सेम्पशन्स मिल सकते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहता है, लेकिन उसे इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक बैलेंस भी बनाना होगा।

यह समय भारत के लिए नई मार्केट्स तलाशने और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने का है। क्या भारत इस चैलेंज को ऑपर्च्युनिटी में बदल पाएगा? यह आने वाले महीनों में साफ होगा।

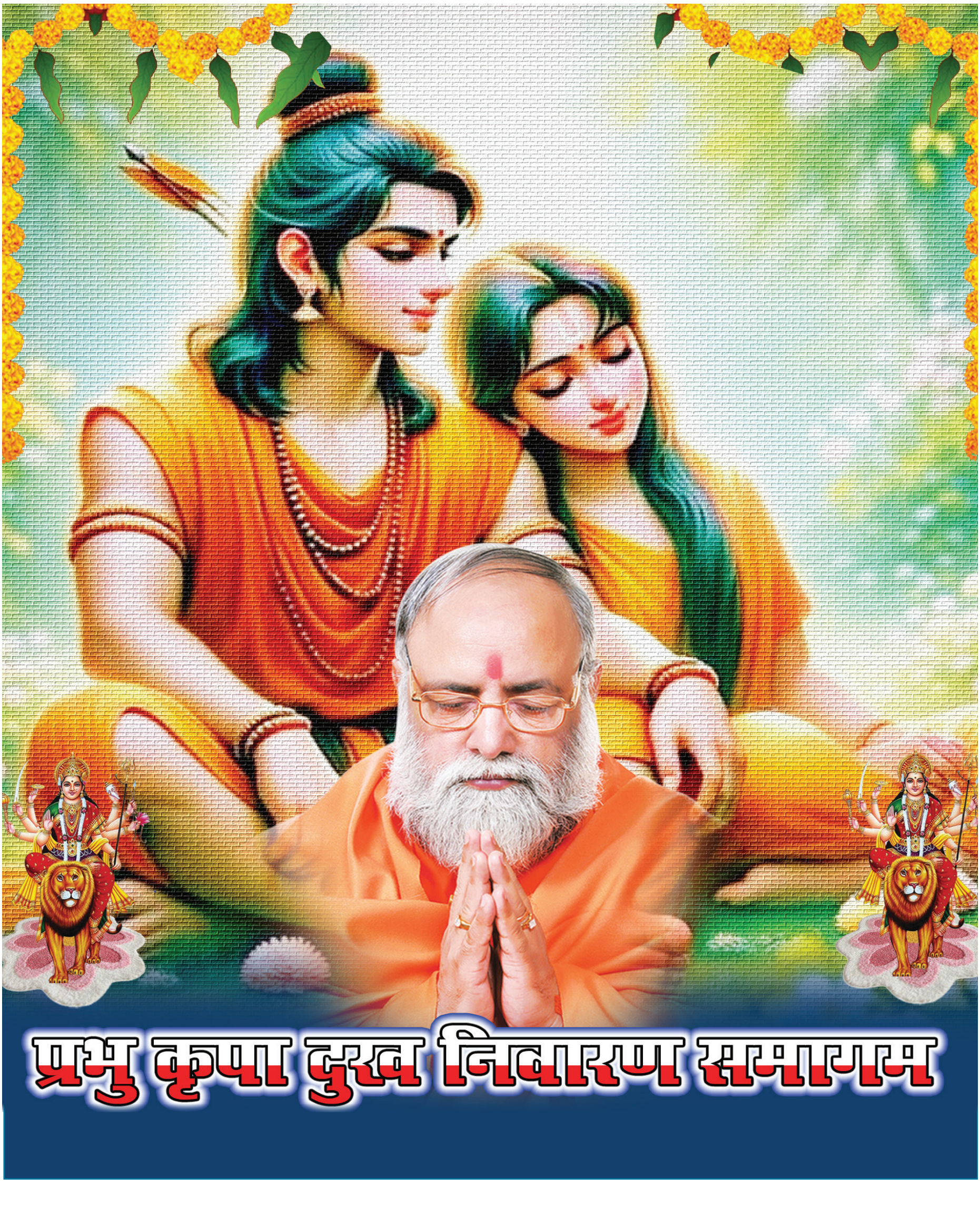
प्रभु कृपा दुख निवारण समागम

BY

Arihanta Industries

ULTIMATE HAIR SOLUTION

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML

15 ML

NO ARITIFICIAL COLOR FRAGRANCE CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.

ORDER ONLINE @ :

amazon

arihanta.in

Arihanta Industries